केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

16 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

मालवा हेराल्ड

वर्ष : 16 अंक : 210 | उज्जैन, शुक्रवार 9 जनवरी 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपए

महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

सुविचार

अच्छे विचारों का असर आज कल इसलिए कम होता है, क्यों की लिखने वाले और पढने वाले दोनो ये समझते है कि ये दुसरों के लिए है।

राष्ट्रीय सम्मेलन में तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिवादन

भारत का वस्त्र उद्योग- विकास, विरासत और नवाचार का ताना-बाना की थीम पर गुवाहाटी में शुरू हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगारपरक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश को औद्योगिक और निवेश की दृष्टि से उल्लेखनीय सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने जन्मदिवस पर मध्यप्रदेश के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन किया। यहां टेक्सटाइल पार्क और उद्योगों का एक साथ लोकार्पण किया जाएगा। यह पार्क भारत को सशक्त बनाने के संकल्प की पूर्ति भी करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आर्थिक रूप से तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने के ओर अग्रसर है। मां कामाख्या की धरती असम से आज देश के वस्त्र उद्योग को नई दिशा प्राप्त होगी। सभी राज्यों में वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत का वस्त्र उद्योग- विकास, विरासत और नवाचार का ताना-बाना की थीम पर आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कृति, संस्कार, संसाधन और विरासत की दृष्टि से मध्यप्रदेश, टेक्सटाइल सहित अनेक उद्योगों में देश में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक गतिविधियां और निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत संभाग और जिला स्तर पर भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उज्जैन, रीवा, कटनी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में औद्योगिक विकास से जुड़ी गतिविधियों का विस्तार हुआ है। प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई के काल से महेश्वरी, चंदेरी साड़ी जैसे सिल्क को प्रोत्साहित करने की परंपरा है। राज्य सरकार ने नर्मदापुरम के हाईक्वालिटी मलबरी रेशम और ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। मध्यप्रदेश में हम टेक्सटाइल मिल, लूम हैंडलूम और स्पिंडल्स से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़कर आत्म निर्भर बनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मेनमेड फाइबर, टेक्नीकल टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के खरगोन, बुधनी सहित जनजातीय बहुल इलाकों में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में डेढ़ दशक से चल रही टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन में राज्य सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश कराया है। भविष्य में इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश नए संकल्पों के साथ विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी जुलाई 2026 में भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में मध्यप्रदेश सरकार पार्टनर बनने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है, उन्होंने केंद्रीय वस्त्र मंत्री को अगला सम्मेलन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में करने के लिए आग्रह किया।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रदेश में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में की जा रही पहल के लिए सराहना की। धार में बन रहे देश के पहले पीएम मित्रा पार्क के निर्माण में तेजी से हो रहे कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिवादन किया। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आने से वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में चार चांद लग गए हैं। उन्होंने कहा कि वस्त्र मंत्रालय, मध्यप्रदेश में दो तरह के फाइबर पर कार्य करना चाहता है। पहला- लीनन जो अलसी में होता है और दूसरा- मिल्क बिल्ट (मदार) फाइबर। केंद्र सरकार न्यू एज फाइबर को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने राज्यों से टेक्सटाइल का रोडमैप बनाकर गतिविधियां संचालित करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य टेक्निकल फाइबर को उतनी ही महत्ता दें, जितनी मशीन मेड फाइबर को दी जाती है।

न्यूज ब्रीफ

नकली नौकरी और सैलरी के लालच से बचना! देश के 15 ठिकानों पर पटना ईडी की रेड

पटना/ जीएनएस। रेलवे समेत अन्य सरकारी महकमों में नौकरी दिलाने के नाम पर चलाए जा रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को संगठित गिरोह के ठिकानों पर एकसाथ छापे मारे। पटना जोनल कार्यालय ने बिहार में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के साथ ही पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में एक साथ 15 स्थानों पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी के पास प्रमाण थे कि एक गिरोह लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा था। शुरुआती जांच में यह घोटाला भारतीय रेल के नाम पर सामने आया था, लेकिन ईडी की विस्तृत जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क 40 से अधिक सरकारी संगठनों और विभागों के नाम पर फर्जी नियुक्तियां दे रहा है। ईडी सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने पुख्ता प्रमाण के बाद मामले की जांच शुरू की थी। जिसमें यह बात सामने आई कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह ने सरकारी डोमेन से मिलते-जुलते फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे। इन ईमेल आईडी को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे असली सरकारी ईमेल जैसी दिखें। इससे अभ्यर्थियों का भरोसा और मजबूत हो जाता था। घोटाले की सबसे खतरनाक रणनीति यह थी कि गिरोह कुछ पीड़ितों को दो-तीन महीने तक शुरुआती वेतन भी देता था। इन युवाओं को भारतीय रेल में आरपीएफ, टीटीई, टेक्नीशियन जैसे पदों पर तैनाती का दिखावा किया जाता था। वेतन मिलने के बाद पीड़ितों को नौकरी पक्की लगने लगती थी। इसके बाद संबंधित लोगों से मोटी रकम वसूली जाती थी। ईडी को अपनी जांच में यह प्रमाण भी मिले कि संगठि रूप से चलाए जा रहे गिरोह ने भारतीय रेल के अलावा वन विभाग, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), भारतीय डाक, आयकर विभाग, हाई कोर्ट, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), बिहार सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), राजस्थान सचिवालय समेत कई प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों के नाम का दुरुपयोग किया। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर इतने पेशेवर तरीके से तैयार किए जाते थे कि सामान्य अभ्यर्थी आसानी से इनके जाल में फंस जाते थे।

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में छह और गिरफ्तार, 40 से अधिक संदिग्ध हिरासत में

नई दिल्ली/ जीएनएस। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज-ए-इलाही के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर पथराव और दंगा करने के आरोप में छह और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान तुर्कमान गेट के अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अथर और उबैद के रूप में हुई है। हिंसा भड़काने के आरोप में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 40 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा, दंगाइयों की पहचान करने के लिए ड्रोन, 400 से ज्यादा CCTV कैमरों और बॉडी-वर्न कैमरों की फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को दूसरे दिन भी दरगाह फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा। मस्जिद से सटी कुछ अवैध संरचनाएं जिन्हें मंगलवार को पूरी तरह से नहीं गिराया गया था, उन्हें गुरुवार को बुलडोजर और क्रेन की मदद से जमींदोज कर दिया गया। मौके से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है।

37 लाख लोगों को बनाया निशाना, 54 की हो गई मौत; आवारा कुत्तों के काटने का पूरा आंकड़ा

नई दिल्ली/ जीएनएस। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई चल रही है। इस मामले पर सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारा शामिल है।स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी के मामले को लेकर अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि क्या इन जगहों पर कुत्तों की मौजूदगी होनी चाहिए? पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने देशभ में कुत्तों को लेकर चल रहे मामले को अपने यहां मंगवा लिया था, जिस पर एक साथ सुनवाई हो रही है।

सरकार ने लोकसभा में कुत्तों पर क्या जानकारी दी- मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कुत्ता काटने की समस्या को लेकर बीते साल चार फरवरी को लोकसभा में जानकारी दी थी। उन्होंने डीएमके के अरुण नेहरू के सवाल के जवाब में बताया था कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक देश के ग्रामीण इलाकों में कुत्ता काटने की कुल 21 लाख 95 हजार 122 घटनाएं दर्ज की गई थी।

उन्होंने बताया था कि देश के ग्रामीण इलाकों में कुत्तों के काटने से 37 इंसानों की मौत के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं, दूसरे जानवरों के काटने की पांच लाख चार हजार 728 मामले सामने आए थे। इन जानवरों के काटने से 11 लों की मौत होने की जानकारी सरकार ने लोकसभा में दी थी। सरकार ने बताया था कि इस दौरान आवारा कुत्तों ने 15 साल से कम आयु के पांच लाख 19 हजार 704 बच्चों को काटा था।

देशभर में आवारा कुत्तों के काटने के कितने मामले आए- वहीं प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरो की 1 अप्रैल 2025 के एक बयान के मुताबिक, 2024 में देश भर में कुत्तों के काटने के कुल 37 लाख 15 हजार 713 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले 2023 में कुत्तों के काटने के 30 लख 52 हजार 521 मामले देशभर में दर्ज किए गए थे। इस तरह एक साल में देश में कुत्ता काटने के मामलों में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुत्ता काटने के मामले में देश भर में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां कुत्ता काटने के चार लाख 85 हजार 345 मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में चार लाख 80 हजार 427 मामलों के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर था। तीन लाख 92 हजार 837 मामलों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर था। वहीं, लक्षद्वीप देश में एक ऐसी जगह थी, जहां कुत्ता काटने का कोई मामला सामने नहीं आया था।

अनार और आलू के किसानों के लिए खुशखबरी, रूस संग भारत की नई दोस्ती का अध्याय शुरू

नई दिल्ली/ जीएनएस। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) के चेयरमैन अभिषेक देव ने बताया कि रूस के बाजार में अब भारतीय अनार और आलू का निर्यात किया जा सकेगा। रूस ने इसकी मंजूरी दे दी है। एपिडा गैर बासमती चावल के साथ अल्कोहलिक पेय पदार्थ और केला, आम जैसे फल के निर्यात को बढ़ाकर कृषि निर्यात को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है।

यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-नवंबर में कृषि निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी है जबकि इस अवधि में वस्तुओं के कुल निर्यात में 2.5 प्रतिशत का ही इजाफा हुआ है। कृषि व प्रोसेस्ड फूड निर्यात के प्रोत्साहन के लिए ट्रेड प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से आयोजित इंडसफूड 2026 मेले में देव ने कहा कि एपिडा ने एग्रीटेक व एग्रीफूड स्टार्टअप को समर्थन देने की पहल की है ताकि नए उद्यमी निर्यात को लेकर प्रेरित हो सके।

मिडिल ईस्ट देशों में धुरंधर पर लगे बैन को हटाने की अपील, IMPPA ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली/ जीएनएस। विश्व में 1220 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म धुरंधर पर खाड़ी देशों में प्रतिबंध के खिलाफ भारतीय मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने अपनी आवाज उठाई है।

IMPPA ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के अन्य देशों में हिंदी फिल्म धुरंधर पर लगे एकतरफा प्रतिबंध के खिलाफ हस्तक्षेप करने की अपील की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में IMPPA ने कहा कि फिल्म को यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद प्रतिबंधित किया गया। अब इन अरब देशों के धुरंधर पर लगाए गए एकतरफा प्रतिबंध में हस्तक्षेप करें।

यह पत्र केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी भेजा है।

दस्तावेज चोरी हो गए, I-PAC चीफ के परिवार ने जांच एजेंसी ED पर लगाया बड़ा आरोप

नई दिल्ली/ जीएनएस। छापेमारी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के परिवार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ गुरुवार शाम में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आज उनके घर पर हुई तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए। पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, सुबह से करीब नौ घंटे की तलाशी अभियान के बाद, प्रतीक जैन की पत्नी कोलकाता के शेक्सपियर सरणी थाने गईं और ईडी पर दस्तावेजों की चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छापेमारी के दौरान उनके घर से आवश्यक दस्तावेज चोरी हो गए।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच - अधिकारी ने कहा, हमें ईडी के खिलाफ चोरी की औपचारिक शिकायत मिली है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

ममता बनर्जी के साथ है आई-पैक का अनुबंध- मालूम हो कि आई-पैक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार व चुनावी प्रबंधन के रूप में काम कर रही थी।

तनाव के बावजूद भारत के सहारे बांग्लादेश, खरीदेगा 180000 टन डीजल; 14 अरब टका का खर्चा

नई दिल्ली/ जीएनएस। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बावजूद, बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत की सरकारी तेल कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 180,000 मीट्रिक टन डीजल आयात करने का फैसला किया है। इस आयात की कुल लागत लगभग 14.62 अरब टका होगी जो अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ बदल सकती है। यह सौदा 2026 के लिए हुआ है।

यह फैसला 6 जनवरी को ढाका में हुई सरकारी खरीद सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने की। सरकार संचालित बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) इस डीजल का आयात करेगी। भुगतान का कुछ हिस्सा बीपीसी अपने बजट से करेगी, जबकि शेष राशि बैंक लोन के माध्यम से जुटाई जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, आयात लागत एनआरएल के साथ बातचीत के बाद तय की गई है। असम स्थित एनआरएल ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इस सौदे की कुल वैल्यू 119.13 मिलियन डॉलर तय की गई है, जो 83.22 डॉलर प्रति बैरल की बेस कीमत पर 5.50 डॉलर प्रति बैरल के प्रीमियम पर आधारित है। अंतिम लागत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार बदलती रहेगी।

पत्रकारों के सवालों के जवाब में बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन सलाहकार मुहम्मद फौजुल कबीर खान ने कहा कि यह आयात पिछले सरकार के कार्यकाल में हस्ताक्षरित 15 वर्षीय दीर्घकालिक समझौते के तहत किया जा रहा है।

सवालों के बीच दुनिया को इलेक्शन कराने के गुर सिखाएगा चुनाव आयोग, भारत मंडपम में आयोजन

नई दिल्ली/ जीएनएस। भारत निर्वाचन आयोग दुनिया के विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन संस्थानों को अपने अनुभव साझा करने जा रहा है। आयोग 21 से 23 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहला इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट आयोजित करने जा रहा है। यह भारत द्वारा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पहले, चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिल्ली में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में वैश्विक सम्मेलन में उनके नेतृत्व में संचालित होने वाले 36 थीमैटिक ग्रुप्स पर विस्तार से चर्चा की गई।

आधिकारियों के अनुसार, ये थीम चुनाव प्रबंधन के सभी पहलुओं को कवर करती हैं और चुनाव प्रबंधन निकायों के समृद्ध एवं विविध अनुभवों पर आधारित ज्ञान के भंडार का विकास करने का उद्देश्य रखती हैं। ये 36 थीमैटिक ग्रुप्स राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के नेतृत्व में संचालित होंगे, जिनमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञ भी योगदान देंगे।

यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक चुनावी चुनौतियों पर साझा समझ विकसित करना, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों का आदान-प्रदान करना तथा समाधानों का सह-निर्माण करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में यह सम्मेलन भारत के अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल IDEA के 2026 के लिए काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद आयोजित हो रहा है।

चायनीज मांझा बेचने वालों पर चंदननगर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 2.46 लाख रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर में प्रतिबंधित चायनीज मांझे के खिलाफ चंदननगर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस उपायुक्त जोन-04 आनंद कलादगी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दीशेष अग्रवाल एवं सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा शिवेन्दु जोशी के नेतृत्व में थाना प्रभारी चंदननगर इंद्रमणी पटेल द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 8 जनवरी 2026 को पुलिस ने चायनीज मांझा बेचने व परिवहन करने वाले दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम थाना क्षेत्र में इलाका भ्रमण पर थी, तभी चंदननगर चौराहे पर एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की कार में कुछ लोग प्रतिबंधित चायनीज मांझा लेकर चंदननगर से धार की ओर जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस ने बताए गए वाहन क्रमांक MP09CM0724 को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर तेज गति से नावदापंथ की ओर भाग निकला। पुलिस टीम ने दोपहिया वाहनों की मदद से पीछा करते हुए प्रतापनगर के सामने धार रोड पर उक्त कार को रोक लिया।

कार की जांच करने पर ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम करण मेहता पिता देवीलाल मेहता उम्र 25 वर्ष और उसके साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक मेहता पिता देवीलाल मेहता उम्र 24 वर्ष, दोनों निवासी दिलावरा रोड कुमार गड्डा थाना कोतवाली जिला धार बताया। वाहन की तलाशी लेने पर डिक्की में एक सफेद प्लास्टिक का कार्टन मिला, जिसमें खांकी रंग का बक्सा रखा हुआ था। बक्सा खोलकर देखने पर उसमें 46 नग चायनीज मांझे की गिरी पाई गई। जांच के दौरान एक गिरी खोलकर धागा खींचकर देखा गया, जो अत्यंत मजबूत पाया गया और चायनीज मांझा होने की पुष्टि हुई।

पुलिस ने आरोपियों से मांझा रखने व परिवहन करने का लाइसेंस या परमिट पूछने पर उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों को बताया गया कि इंदौर शहर में चायनीज मांझा पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे पतंग उड़ाने के दौरान गला, कान, नाक जैसे कोमल अंगों पर गंभीर चोट लगने व मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सफेद रंग की अल्टो 800 कार, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई गई है, तथा 46 नग प्रतिबंधित चायनीज मांझा जिसकी कीमत लगभग 46 हजार रुपये है, कुल 2 लाख 46 हजार रुपये का मशरूका विधिवत जप्त किया। जप्त सामग्री को सील बंद कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 223(ए) व 125 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चूंकि मामला जमानती एवं सात वर्ष से कम सजा का है, इसलिए आरोपियों को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत सूचना पत्र तामील कराया गया है। मामले की विवेचना जारी है।

इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदननगर इंद्रमणी पटेल, उप निरीक्षक साबिर मंसूरी सहित प्रधान आरक्षक प्रदीप, बलराम तथा आरक्षक धीरज, अनिल और सुनील की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चायनीज मांझे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और प्रतिबंधित सामग्री बेचने या उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए पार्किंग स्थलों का निर्धारण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इन्दौर के होल्कर स्टेडियम में 18 जनवरी को भारत एवं न्यूजीलैण्ड के मध्य एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा। इस मैच में आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए पार्किंग स्थलों का निर्धारण किया गया है। दर्शक अपने वाहनों की पार्किंग एसजीएसआईटीएस परिसर के मैदान तथा बाल विनय मंदिर परिसर में कर सकेंगे। उक्त स्थानों पर एमपीसीए द्वारा पार्किंग हेतु समतलीकरण, साफ-सफाई व्यवस्था, बेरिकेटिंग, पार्किंग स्थल पर बैनर, पार्किंग स्थल पर पहुंचने हेतु दिशा सूचक फ्लेक्स, रोशनी, बैनर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेंगी।

पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये स्कूल और कॉलेजों में 9 और 10 जनवरी को विशेष शिविर होंगे आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026 के अन्तर्गत एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि पर पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिये विशेष शिविर आयोजित होंगे। यह विशेष शिविर जिला स्तर पर 09 एवं 10 जनवरी को हायर सेकेण्डरी स्कूलों, महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थाओं आदि में आयोजित किये जाएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें निर्देशित किए गए है कि उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर आयोजित कर सभी पात्र विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाये। इस संबंध में सभी हायर सेकेण्डरी स्कूल, महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए विशेष शिविर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित किये जाने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, महाविद्यालय स्तर पर अपर संचालक उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय /प्रशिक्षण केन्द्र आदि हेतु कुल सचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियुक्त नोडल अधिकारी संबंधित विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क स्थापित कर निर्धारित तिथि पर कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर पात्र नये युवाओं जिनके नाम दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक नामावली में नहीं है, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे।

अजा-जजा के युवाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष-2027 में आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा की प्रारंभिक और मुख?य परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जायेगी। इसके ?लिये आवेदन 27 फरवरी तक जमा किये जा सकतें है। कोचिंग कक्षाएं 3 मई 2026 से प्रारंभ होगी।

शासकीय पूर्व परीक्षण केन्द्र में यह कोचिंग दी जायेगी। केन्द्र की प्राचार्य तथा सहायक आयुक्त श्रीमती आशा चौहान ने बताया कि आवेदक को मध्यप्रदेश राज्य का अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग से होना चाहिए। समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक न हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकत्तम आयु 35 वर्ष होना तथा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु स्नातक में 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। उक्त प्रशिक्षण की संभावित तिथि 03 मई 2026 है। पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन संस्था से शीघ्र प्राप्त कर, उसकी प्रतिपूर्ति कर आवश्यक डॉक्युमेंट संलग्न कर 12 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक संस्थान में जमा कर सकतें है।

छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता उपस्थिति के आधार पर देय होगी। केन्द्र में सर्व सुविधायुक्त पुस्तकालय है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की पुस्तकें हैं, जिनका प्रशिक्षणार्थी लाभ ले सकते हैं। केन्द्र में कम्प्यूटर लेब की सुविधा भी उपलब्ध है। केन्द्र में योग्य एवं अनुभवी अतिथि प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में प्री / मेन्स के साथ साक्षात्कार के भी प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

Water Audit ने खोली स्वच्छता के दावों की पोल, इंदौर में ज़हर बन चुका है नल का पानी — सबसे स्वच्छ शहर दावा बेनकाबः उमंग सिंघार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में सामने आए जल-प्रदूषण कांड और उसके बाद किए गए Water Audit के निष्कर्ष सार्वजनिक करते हुए भाजपा सरकार और शहरी प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर को बार-बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित करने के दावे ज़मीनी हकीकत में पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि शहर के कई इलाकों में नलों से दूषित, बदबूदार और सीवेज मिला पानी आ रहा है, जो लोगों के जीवन के लिए खतरा बन चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को उन्होंने भगीरथपुरा क्षेत्र का दौरा किया, जहां हालात बेहद भयावह हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार अब तक लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित इलाकों में जाने से रोकने की कोशिश की गई, जगह-जगह पुलिस बैरिकेटिंग लगाई गई और पूरे क्षेत्र को मानो सील कर दिया गया। पुलिस का रवैया व्यवस्था बनाए रखने से अधिक विपक्ष और सच्चाई को रोकने जैसा नजर आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते शोक-संतप्त परिवारों के साथ खड़े होने पहुंची थी। कई पीड़ित परिवार दबाव में दिखे और खुलकर बोलने से डरते नजर आए। आज भी कुछ क्षेत्रों में नलों से वही गंदा पानी आ रहा है और मुआवजे, इलाज व भविष्य की सुरक्षा को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है, लेकिन सरकार इस गंभीर संकट पर आंख मूंदे बैठी है।

उमंग सिंघार ने बताया कि 7 जनवरी 2026 को इंदौर के कई इलाकों में Water Audit किया गया, जो केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि नलों तक जाकर पानी की वास्तविक स्थिति देखने का प्रयास था। इस दौरान मदीना नगर, खजराना, भूरी टेकरी, बर्फानी धाम, कृष्णा बाग और कनाडिया जैसे इलाकों का निरीक्षण किया गया, जो भगीरथपुरा से 5 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये वही इलाके हैं जहां शहर का गरीब, मजदूर और मेहनतकश वर्ग रहता है, जो दिनभर की मेहनत के बाद कम से कम साफ पानी की उम्मीद करता है।

Water Audit के दौरान सामने आए तथ्य बेहद चिंताजनक बताए गए। कई इलाकों में पानी में गंदगी, तेज बदबू और असामान्य रंग पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा पानी पीने के बाद उल्टी, दस्त और पेट की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। कुछ स्थानों पर सीवेज की मिलावट साफ तौर पर नजर आई। हालात ऐसे थे कि पानी पीना तो दूर, उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल था। कई जगह माताएं और बहनें रो-रोकर अपनी पीड़ा बयान करती दिखीं।

नेता प्रतिपक्ष ने क्षेत्रवार स्थिति बताते हुए कहा कि मदीना नगर में कथित बकाया के नाम पर भारी वसूली की जा रही है, लेकिन नियमित बिल चुकाने के बावजूद लोगों को गंदा पानी मिल रहा है और शिकायतों के बाद भी निगम व जनप्रतिनिधि नदारद हैं। खजराना में नर्मदा जल में तेज बदबू और प्रदूषण पाया गया, पानी पीने योग्य नहीं है और समस्या पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि कार्रवाई बेहद सीमित है। भूरी टेकरी में पानी अत्यधिक दूषित और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वर्षों से शिकायतें होने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकला। कृष्णा बाग में पेयजल पाइपलाइन गटर के पास से गुजर रही है, जिससे सीवेज मिलावट का गंभीर खतरा बना हुआ है। बर्फानी धाम और कनाडिया में भी दूषित पानी, अव्यवस्थित जल वितरण और प्रशासन की उदासीनता साफ नजर आई।

उमंग सिंघार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्ष 2026 में, आज़ादी के 79 साल बाद भी नागरिक साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस देश ने अंतरिक्ष तक उड़ान भरी है, उसी देश में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तथाकथित विकसित भारत के दावों पर करारा तमाचा है। शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर, कीचड़, खुले नाले, गड्ढों से भरी सड़कें और अधूरे निर्माण कार्य प्रशासनिक विफलता को उजागर करते हैं, जो बारिश के मौसम में और भी भयावह हो जाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या यही देश का सबसे साफ शहर है। उन्होंने याद दिलाया कि इंदौर को लगातार आठ बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और वर्ष 2025 में भी शीर्ष स्थान मिला, जबकि नगर निगम का बजट 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद नागरिकों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि दीवारों पर अवॉर्ड टंगे हैं और नालों में ज़हर बह रहा है। अगर लोग सीवेज मिला पानी पीने को मजबूर हैं, तो ऐसी स्वच्छता रैंकिंग का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि स्वच्छता के अवॉर्ड से लोग ज़िंदा नहीं रहते, ज़िंदा रहने के लिए साफ पानी चाहिए, जो मौजूदा सरकार देने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि Water Audit ने साफ कर दिया है कि इंदौर का जल संकट कोई अपवाद नहीं, बल्कि भाजपा के शहरी शासन मॉडल की असफलता है। जब तक साफ पानी, जवाबदेही, पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत से उठाता रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि नगर निगम के अधिकारियों और महापौर सहित सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सौ करोड़ रुपये की बेशकीमती शासकीय भूमि करायी गई अतिक्रमण मुक्त

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए इंदौर जिले में अभियान चलाकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में आज जिला प्रशासन के अमले ने दो स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सौ करोड़ रुपये से अधिक कीमत की बेशकीमती शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त करायी। ग्राम खजराना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 296 रकबा 0.769 हेक्टेयर भूमि जो की शासकीय भूमि है, के पैकी भाग क्षेत्रफल लगभग 35 हजार वर्गफीट के पैकी भाग पर इमरान पटेल द्वारा रूम निर्मित कर भैंस का तबेला बनाया गया था एवं शाकीर शाह द्वारा गैरेज का निर्माण किया गया था, को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त भूमि का बाजार मूल्य लगभग 52 करोड़ 50 लाख रुपये है। इसी तरह शासकीय शहरी सीलिंग भूमि सर्वे नम्बर 325/1/6/2 से भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस भूमि का कुल रकबा 45 हजार वर्गफीट है। इस भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गए फेंसिंग एवं निर्माण को हटाया गया। उक्त दोनों भूमि का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है।

परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं, 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए तैयार रहें : सुश्री सारिका घारू

दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर विद्यार्थियों से पूर्व-परीक्षा लाइव संवाद

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किए जाने वाले 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम से पूर्व दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सुश्री सारिका घारू ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से लाइव संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को परीक्षा तनाव से मुक्त रहने, सकारात्मक सोच अपनाने और तकनीक के संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को बोझ न मानकर अपने ज्ञान और क्षमता को परखने का अवसर समझना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' में भाग लें।

परीक्षा से पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर लक्ष्य पर फोकस रखने की बात पर जोर देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी आज के समय में एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसका सही उपयोग आवश्यक है। तकनीक को परीक्षा की तैयारी और सीखने के लिए एक टूल बनाएं, न कि ध्यान भटकाने का माध्यम। सुश्री सारिका घारू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पहल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी से इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी कर प्रधानमंत्री के अनुभवों से सीख लेने का आग्रह किया।

शासकीय कार्यालयों में शासकीय सेवकों को निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य

समय पर नहीं पहुँचने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध होगी कार्रवाई

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार शासकीय कार्यालयों में शासकीय सेवकों को निर्धारित समय पर पहुँचना अनिवार्य होगा। समय पर कार्यालय नहीं पहुँचने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया है कि वे सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहे तथा निर्धारित समय शाम 6 बजे पर ही कार्यालय से जाए।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर आज कलेक्टर कार्यालय में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कलेक्टर श्रीमती कल्याणी पांडे ने कलेक्टर कार्यालय स्थित विभागों महिला बाल विकास विभाग, जिला कोषालय, खनिज कार्यालय, भू अभिलेख , सामाजिक न्याय विभाग एवं अन्य सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों के उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए गए। साथ ही समय पर नहीं पहुँचने वाले शासकीय सेवकों को हिदायत दी गई कि वे भविष्य में प्रतिदिन समय पर कार्यालय आए और समय पर ही कार्यालय छोड़े। समय पर नहीं पहुँचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्र में गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग ने 1750 घरों में वितरित किये किट

प्रभावित क्षेत्र में उल्टी-दस्त से बचाव के बारे में लगातार किया जा रहा है जागरूक

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई जलजनित घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किए जा रहे कार्यों से स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भागीरथपुरा के प्रभावित क्षेत्र में सघन दौरा किया। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भागीरथपुरा के प्रभावित क्षेत्रों में उल्टी दस्त के जो मरीज स्वस्थ होकर लोटे थे, उनका फालोअप किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरूवार को भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्र में 1750 घरों में किट प्रदान की गई, जिसमें लगभग 6245 सदस्य लाभांवित हुए। प्रत्येक किट में 10 पैकेट ओ.आर.एस. तथा 30 गोलियां जिंक की हैं।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार क्षेत्र में 02 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। 24×7 चिकित्सकों की ड्यूटी क्षेत्र में लगाई गई है। मरीजों को एमवाय चिकित्सालय, अरविंदों अस्पताल तथा बच्चों को चाचा नेहरु अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। जो मरीज निजी चिकित्सालयों में जा रहें हैं, वहाँ पर भी निःशुल्क उपचार, जॉच एवं औषधि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा करायी गई है। गुरूवार को प्रभावित क्षेत्र में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें उल्टी-दस्त से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। गुरूवार की शाम तक डायरिया के 23 मरीज ओ.पी.डी. में आए, जिसमें से 06 रेफरल किए गए है। ओ.पी.डी. में आए मरीजों में यह भी पाया गया है कि मरीज दवाईयों का डोज पूरा नहीं कर रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने प्रभावित क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दवाईयों का डोज आवश्यक रूप से पूर्ण करें। वर्तमान में अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 50 है। जिसमें से आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या 10 है।

किसानों को अब ई-टोकन से मिलेगा खाद

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राज्य शासन के निर्देशानुसार किसानों को सरलता, सुलभता एवं रियल टाइम पारदर्शिता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-विकास प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से किसानों को ई-टोकन से खाद का वितरण किया जाएगा। इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संभाग के संयुक्त संचालक कृषि, संभाग के समस्त उप संचालक कृषि, क्षेत्रीय प्रबंधक मार्कफेड, क्षेत्रीय प्रबंधक एमपी एग्रो एवं जिला विपणन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, प्रबंधक सहकारी समितियों, विपणन समितियों एवं विपणन संघों से संबंधित गोदाम प्रभारी तथा ऑपरेटर्स उपस्थित रहें। इस दौरान ई-टोकन प्रणाली के तकनीकी पहलुओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के तरीकों पर विस्तृत प्रशिक्षण एवं चर्चा की गई।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री सी.एल. केवड़ा ने बताया कि कृषकों को समयसीमा में पारदर्शिता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा ई-टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है। बताया गया कि कृषक स्वयं भी अपनी सुविधा अनुसार उर्वरक क्रय कर सकते है। इसके लिए किसान अपने मोबाइल के माध्यम से निम्नानुसार प्रक्रिया कर ई-टोकन जारी कर, गूगल पर https://eto-ken.mpkrishi.org लिंक के माध्यम से कृषक अपने आधार नंबर एवं ओटीपी फीड कर लॉग इन कर सकते है।

लॉग इन करने के उपरांत पोर्टल पर एग्री स्टैक (फार्मर आई.डी.) से कृषि भूमि अपडेट होकर, मौसम एवं फसल का चयन करने के उपरांत फसल तथा कृषि भूमि अनुसार वैज्ञानिक आधार पर उर्वरको की गणना होकर पोर्टल पर स्वतः अपडेट होगी, उसके बाद यदि कृषक सहकारी समिति के सदस्य है या नहीं का चयन करेंगे, पोर्टल पर प्रदर्शित होने के उपरांत कृषक भाई उर्वरक विक्रेता मार्कफेड, एम.पी. एग्रो, विपणन समिति एवं निजी उर्वरक विक्रेताओ के यहाँ उपलब्ध स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमे किसान अपनी सुविधा अनुसार उर्वरक विक्रेताओ का चयन कर ई-टोकन जारी हो जायेगा। किसान चयनित उर्वरक विक्रेताओ के यहाँ से 3 दिन के अंदर उर्वरक क्रय कर सकते है। किसान विक्रेता के यहां जायेगे तो विक्रेता द्वारा मोबाईल ऐप से किसान का ई-टोकन स्कैन किया जायेगा और उर्वरक वितरण की पुष्टि की जाएगी। किसान उर्वरक प्राप्ति के बाद किसानों को SMS एवं WhatsApp के माध्यम से भी भुगतान रसीद प्राप्त होगी। यदि किसी किसान द्वारा 3 दिन के अंदर खाद क्रय नहीं किया जाता है, तो टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में 3 दिन के बाद दोबारा ई-टोकन जनरेट करना होगा।

जिले में विगत दिवस समस्त पंजीकृत थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को भी इस प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें खुदरा स्तर पर ई-विकास प्रणाली के प्रयोग, किसानों की सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया और सिस्टम में होने वाली संभावित चुनौतियों के समाधान पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

मास्टर प्लान और मंदसौर सीएमओ की कार्यप्रणाली पर सख्त हुए सांसद सुधीर गुप्ता

सभी जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की, दिशा समिति की बैठक संपन्न

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय मंदसौर में हुई। बैठक में मंदसौर सीएमओ और शामगढ़ सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। मास्टर प्लान की विसंगतियों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किए। इसी के साथ ही एनएचएआई विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति को लेकर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

गुरूवार को जिला कलेक्टर भवन में सांसद गुप्ता की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में करीब 54 विभागों के विकास कार्यो को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में 150 करोड़ के सीवरेज प्लान को लेकर सीएमओ अनीता चौखटिया कोई जानकारी नही दे पाई। जिसको लेकर सांसद गुप्ता ने उन पर नाराजगी जाहिर की। बिना जनप्रतिनिधियों की जानकारी के अभाव में सीवरेज कार्य की शुरूआत भी कर दी गई। सांसद गुप्ता ने कहा कि किस मानक की जनसंख्या के आधार पर सीवरेज प्लान को लेकर कार्य कर रहे इसको लेकर भी अधिकारी कोई ठोस जवाब नही दे पाएं। सांसद गुप्ता ने अधिकारियों को कार्य रोकने की बात कही। साथ ही एक सप्ताह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर पूरी जानकारी के साथ चर्चा करने की बात कही।

सांसद गुप्ता ने सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर भी कहा कि जनता की समस्याओं में आपका कोई रूझान नही है। जनप्रतिनिधियों से आपका कोई नही तालमेल नही है। ईट भट्टो संचालको और व्यापारियों की दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाएं जाने

को लेकर सांसद गुप्ता ने सीएमओं पर सख्त हुए और उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी इसको अमानवीय बताया। सांसद गुप्ता ने कहा कि इतनी क्या जल्दी थी कि उनको बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई। इस पर सीएमओ तहसीलदार का कहकर मामले को टालते नजर आई। वहीं शामगढ़ सीएमओ सुरेश यादव को अमृत योजना के तहत 7 करोड़ की सीवरेज योजना को लेकर कोई जवाब नही दे पाए जिसके बाद उन पर कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए नाराजगी जाहिर की।

बैठक में मास्टर प्लान 2041 को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होने इसमें विसंगतियों को लेकर कई सवाल अधिकारियों से किए। सांसद गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका सीएमओ 2041 तक 2 लाख 35 हजार की आबादी की बात कह रही और टीएनसी विभाग 5 लाख के आधार पर नक्शा बना रहा है। मास्टर प्लान के दोनो कार्यो में मानको के आधार पर सही नही है। मास्टर प्लान में सड़को के चौडीकरण को लेकर भी सांसद गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की। सांसद गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका की बिना अनुमति व मुआवजा दिए बिना सड़को का चौडीकरण कैसे हो सकता है। उन्होने आपत्तियों को लेकर भी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की बात कही। सांसद गुप्ता ने कहा कि बिना नगर पालिका के सड़क, पानी जैसी मूलभूत संरचनाओं को कैसा पूरा कर सकते है। इस पर भी विभागीय अधिकारी कोई ठोस जवाब नही दे पाएं। वहीं 26 ग्रामों को मास्टर प्लान में जोड़े जाने और उनको आवासीय योजना में भी किस प्रकार कार्य किया जाएगा इसको लेकर भी संक्षेय बरकरार है।

इसी के साथ सांसद गुप्ता ने अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए विस्तृत चर्चा की। सांसद गुप्ता द्वारा जावरा नयागांव लेबर रोड़ टोल कंपनी पर वसूली को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। सांसद गुप्ता ने कहा कि मानको के आधार पर टोल कंपनी को 7 प्रतिशत की वृद्धि करना थी लेकिन वर्तमान में वह अधिक वूसली कर रही है। इस पर जांच दल गठन करने और अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने की बात कही। इसी के साथ ही पेड़ काटे जाने और दुर्घटनाओं को लेकर भी सांसद गुप्ता ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। एंबुलेंस भी बिना मापदंड के चल रही जिस पर भी अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। वहीं सड़को के किनारे हो रहे अतिक्रमण को भी चिन्हित करने की बात कही। साईन बोर्ड लगाए जाने, बिना मुंडेर के कुओं और सड़को की गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। दलौदा डिगांव रोड़ में हो रही अनियमितताओं को लेकर भी बात कही। सांसद गुप्ता ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को गलत जानकारी नही देने की बात कही। वहीं पशुपतिनाथ से सक्रिट हाउस रोड़ को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। सांसद गुप्ता ने सड़को, ब्रिज के निर्माणों में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया।

सांसद गुप्ता ने वन विभाग को लेकर कहा कि पर्यटन को लेकर प्रचार प्रसार करे। उन्होने कहा कि बोत्सावना से 8 चीते जल्द ही गांधीसागर में आएंगे। वहीं रोजड़ो से बचाव को लेकर भी अधिकारियों को ठोस नीति बनाने की बात कही। सांसद गुप्ता ने कहा कि रोजड़ो से किसानो को भारी नुकसान होता है इसके लिए बन विभाग व संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई करे। यह गंभीर समस्या है। उन्होने मंडी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडी में हम्मालों को टेम्पो परिवहन किया जाए जिससे किसानों को व्यापारी के यहा तक माल लाने में परेशानियों का सामना नही करना पड़े। इसी के साथ ही मंडी में पोस्तादाना की बिक्री शुरू करने की बात कही। वहीं जिले की अन्य मंडियों में व्यवस्था सुधारने और दलौदा व सुवासरा मंडी की प्रस्तावित भूमि को लेकर आगे की कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्यक्रम करने की बात कही जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी के साथ ही सांसद गुप्ता ने अन्य विभागो की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे सभी निर्माण कार्य जिनमें प्रगति में विलंब हुआ है, उनके संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारी, कार्यदायी एजेंसी तथा थर्ड पार्टी (यदि लागू हो) को विलंब के कारणों सहित बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रखा जाए, ताकि कार्यों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। सभी विभाग सुनिश्चित करें कि वे अपनी-अपनी योजनाओं की पूर्ण जानकारी, अद्यतन स्थिति एवं संबंधित डीपीआर सहित बैठक में प्रस्तुत करें, जिससे योजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय समीक्षा प्रभावी रूप से की जा सके।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैलाश चावला, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, विधायक हरदीप सिंह डंग, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया, जिलाध्यक्ष राजेश दिक्षित, विधायक विपीन जैन, जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, मदनलाल राठौर, हिलालचंद मालवीय, मनुप्रिया यादव, नानालाल अटोलिया, गौरव अग्रवाल, धीरज पाटीदार, गोपाल पटवा, अभिषेक मांदलिया, क्षितिज पुरोहित, सहित स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

पेयजल व्यवस्था को लेकर एक्शन में नगर पालिका

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा शहर में शुद्ध पेयजल वितरण को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है! शहर में स्थापित पेयजल टंकियों में से अब तक 13 पेयजल टंकियां की सफाई करवाई जा चुकी है तथा प्रतिदिन नीमच शहर में वितरण किए जाने वाले पानी की जांच कर शुद्ध पानी वितरण किया जा रहा है!

उपरोक्त जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद नीमच की मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया ने बताया कि नगर पालिका द्वारा हिंगोरिया स्थित फिल्टर प्लांट (जल शुद्धिकरण यंत्रालय)से पानी का शुद्धिकरण कर पेयजल प्रयोगशाला में सैंपल का परीक्षण करने के पश्चात ही शहर में जल वितरण हेतु भेजा जा रहा है! साथ ही प्रतिदिन जल उपभोक्ताओं के यहां से भी पेयजल वितरण के दौरान पेयजल का नमूना लिया जाकर पेयजल प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है!

सीएमओ श्रीमती बामनिया ने बताया कि शहर में केन द्वारा पेय जल वितरण करने वाले संस्थान के यहां से भी शहर में वितरण किए जाने वाले पानी के नमूने लेकर पीएचईडी को परीक्षण हेतु भेजे गए हैं! श्रीमती बामनिया ने बताया कि नीमच शहर में कुल 25 पेयजल टंकियां है जिसमें से 20 उपयोग में आ रही है और उपयोग में आने वाली 13 पेयजल टंकियां की सफाई करवाई जा चुकी है ओर शेष टंकियां की सफाई का कार्य भी जारी है! श्रीमती बामनिया ने बताया कि वर्तमान में गंदे पानी की मात्र एक शिकायत है इसके निराकरण हेतु कार्रवाई प्रचलित है, साथ ही प्रतिदिन लीकेज संधारण का कार्य भी किया जा रहा है! श्रीमती बामनिया ने बताया कि निकाय क्षेत्र में वितरीत किया जा रहा पेयजल पैरामीटर अनुसार जांच में सही पाया गया है!

श्रीमती बामनिया ने शहर के नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि अगर कहीं भी पाइपलाइन लीकेज दिखाई देती है अथवा नलों में गंदा पानी नजर आता है तो उसकी शिकायत तुरंत नगर पालिका में करें ताकि शिकायत का समाधान किया जा सके।

परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाएं नपाध्यक्ष, ड्रेनेज और पेयजल वितरण के सिस्टम की समीक्षा करें

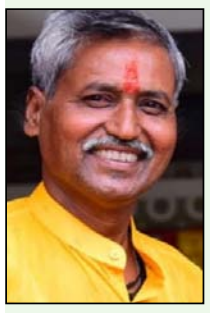

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर की घटना से भी नगर पालिका परिषद मंदसौर ने कोई सबक नहीं लिया मात्र जलकर समिति की मीटिंग बुलाकर इतिश्री कर ली गई। यह आरोप नगर पालिका परिषद में जनता के पार्षद सुनील बंसल ने लगाया। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से मांग की है कि प्रदेश के इंदौर शहर में जो गंदे पानी की घटना हुई है वह निश्चित रूप से अत्यंत दुखद और मानवता को झकझोर देने वाली है ऐसी घटना से हमको सबक लेना चाहिए। देखने में आया है कि मंदसौर शहर के इतिहास में पहली बार कलेक्ट्रेट में होने वाली साप्ताहिक अंतर विभागीय यानी टी एल की मीटिंग नपा में आयोजित की गई। इसी से इंदौर की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है। बंसल ने कहा कि निश्चित रूप से हमें भी पार्षदों की एक मीटिंग आवश्यक रूप से बुलानी चाहिए। नगर पालिका मंदसौर को सिर्फ जलकर समिति की मीटिंग बुलाकर कार्य योजना बनाकर उसे समस्या का निदान नहीं हो सकता। नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका परिषद मंदसौर का विशेष सम्मेलन बुलाकर मंदसौर शहर की विभिन्न क्षेत्रों में जल सप्लाई को लेकर जो परेशानियां है, कहां क्या दिक्कत है ? इन सबकी समीक्षा करनी चाहिए ताकि हम अपना शहर को स्वस्थ रख सके किसी भी जनहानि से हम बच सके।

दिशा बैठक में जिपं अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार का आरोप-नियम विरुद्ध खदानों का आवंटन कर खनिज अधिकारी सेंगर ने किया भ्रष्टाचार!

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। गुरूवार को कलेक्टर कार्यालय मंदसौर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 54 विभागों की समीक्षा की गई। खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार ने मंदसौर जिले में नियम विरुद्ध खदान आवंटन का मुद्दा उठाया, जिला पंचायत अध्यक्ष ने तथ्यों सहित विषय रखते हुए कहा कि 134 करोड रुपए की वसूली लंबित होने के बावजूद एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पुन: खदान आवंटित कर दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। दुर्गा पाटीदार ने आरोप लगाया कि खदान आवंटन में प्रभारी खनिज अधिकारी भावना सेंगर द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के एक पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था कि एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 134 करोड़ रुपए के अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो की वरिष्ठ कार्यालय में प्रचलित हैं कंपनी पर उक्त राशि प्रस्तावित की गई है ना की अधिरोपित, जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरटीआई में प्राप्त की गई एक जानकारी का हवाला देकर कहा कि एमकेसी कंपनी पर पेनल्टी लगने के बावजूद भी उन्हें फिर खदान आवंटित कर दी गई और तथ्यों को छुपाया जा रहा है। खनिज अधिनियम 1996 के नियम 18 और 68 का जो हवाला दिया गया है उनका अध्ययन करने पर यह पाया गया कि प्रभारी खनिज अधिकारी सेंगर लगातार नियमों के विरुद्ध जाकर बड़े-बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है, मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है खनिज खदान आवंटन की जांच उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

मुल्तानपुरा में अवैध खनन का मुद्दा भी उठाया- इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मंदसौर शहर के नजदीक ही ग्राम मुल्तानपुरा में स्लेट पेंसिल की बंद पड़ी खदानों में अवैध खनन का मुद्दा भी उठाया गया। कहा कि मुल्तानपुरा में बंद पड़ी स्लेट पेंसिल की खदानों में प्रतिदिन रात 11 से सुबह 5 बजे तक अवैध खनन होता है, खनिज विभाग की संरक्षण में हो रहे इस अवैध खनन को रोकने के लिए कई बार विषय उठे, किंतु इन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई, साथ ही सामान्य व्यक्तियों को मुल्तानपुरा के निवासियों द्वारा इन खदानों के आसपास भी नहीं जाने दिया जाता एवं उन्हे धमकाकर भगा दिया जाता है, इस संबंध में पुलिस विभाग भी मुक दर्शक बना हुआ है। अवैध खनन से प्राप्त की गई राशि का उपयोग असामाजिक गतिविधियों में संलग्न लोगों को संरक्षण प्रदान करने में किया जा रहा है, जो की कानून व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय है। बैठक में मंदसौर जिले के सभी विधायक गण, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, मनोनीत जनप्रतिनिधि सहित जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला वन मंडल अधिकारी एवं अन्य सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नीमच के लायन डेन में बुद्धि का महासंग्राम, स्व. कश्मीरी लाल अरोरा की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के लायन डेन में आज स्वर्गीय कश्मीरी लाल अरोरा की स्मृति में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ भव्यता और गरिमा के साथ हुआ। यह ऐतिहासिक आयोजन नीमच को अंतरराष्ट्रीय शतरंज मानचित्र पर स्थापित करते हुए खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार अवसर सिद्ध होने जा रहा है।

प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता 5 वर्ष के नन्हे बालक से लेकर 85 वर्ष के वरिष्ठ खिलाड़ी की सहभागिता है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शतरंज उम्र का नहीं, बल्कि बुद्धि, साधना और एकाग्रता का खेल है। नीमच के उभरते खिलाड़ी साहेब सिंह गोत्रा से लेकर झांसी (उत्तर प्रदेश) के 85 वर्षीय आरके गुप्ता की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया है।

डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयरत्न गर्ग एवं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सोनी के नेतृत्व में, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फीडे) के निर्देशन में आयोजित इस टूर्नामेंट में 300 से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी भाग लेकर उच्च स्तरीय मुकाबलों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेंगे। पूरे आयोजन के दौरान खेल भावना, अनुशासन और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

शुभारंभ अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे नीमच के खेल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। समाजसेवी एवं प्रायोजक अशोक अरोरा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से जिले की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। यह टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों को फीडे रेटिंग अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि नीमच को एक सशक्त खेल नगरी के रूप में पहचान भी दिलाएगा।

झांतला मंडल में 11 जनवरी को होगा विराट हिन्दू सम्मेलन 12 गांवों की होगी सहभागिता

भव्य शोभायात्रा के साथ शुरू होगा सम्मेलन

सिंगोली/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रतनगढ़ खंड के मंडल झांतला में 11 जनवरी 2026 को विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।हिन्दू सम्मेलन के निमित्त ग्राम झांतला के सकल हिन्दू समाज की बैठक मुरलीधर धर्मशाला में की गई।जिसमे हिन्दू सम्मेलन को लेकर ,खण्ड कार्यवाह श्रीलाल गुर्जर व उपखण्ड कार्यवाह नन्दकिशोर धाकड़ ने हिन्दू सम्मेलन की आवश्यकता और सार्थकता पर प्रकाश डालकर विस्तृत रुपरेखा बताते हुए हिन्दू सम्मेलन आयोजन समिति का गठन किया गया।जिसमें समिति सयोंजक नेमीचंद धाकड ,सह सयोजक बालकिशन धाकड,मुकेश नाथ योगी को बनाया गया। बैठक में विराट हिन्दू सम्मेलन के लिए लगभग 100 सदस्यों की आयोजन समिति का गठन किया गया। प्रचार-प्रसार एवं जनसंपर्क को प्रभावी बनाने के लिए पीले चावल, पत्रक एवं स्टीकर वितरण का निर्णय लिया गया।स मंडल के सभी लगभग 12 ग्रामों तक निमंत्रण पहुंचाने के लिए टोलियों का गठन किया गया ।ये टोलियां घर-घर संपर्क करेंगी और ग्रामवासियों को सम्मेलन में सहभागी बनने का निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक ग्राम में भगवा पताकाएं लगाई जाएगी।सम्मेलन से पूर्व वाहन रैली का आयोजन होगा।प्रतिदिन श्रीराम संकीर्तन रामधुन निकाली जाएगी।

नपा में उड़ रही महिला सशक्तीकरण की धज्जियां: ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इष्टा भाचावत का आरोप

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भाजपा के नेता अपने भाषणों में महिला सशक्तीकरण के बडे-बड़े दावे करते है। लेकिन मंदसौर में महिला सशक्तीकरण की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संवैधानिक रूप से जो हक महिला जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है।

उक्त आरोप लगाते हुए मंदसौर ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष सुश्री इष्टा भाचावत ने बताया कि मंदसौर नगर पालिका में महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या पुत्र काम काज को संभाल रहे है जिससे न सिर्फ काम काज अवरूद्ध हो रहा है वहीं नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी अहज महसूस करते है। इसी का एक ताजा मामला हाल ही में हमें देखने को मिला जब एक महिला पार्षद के पति ने नगर पालिका के इंजिनियर के साथ मारपीट कर दी और जब पीडित व्यक्ति थाने पहुंचा तो भी उस पर सत्ता का दबाव बनाया गया। सुश्री भाचावत ने बताया कि घटना के तीन दिन बाद भी व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पाई एक पार्षद प्रतिनिधि की गलती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है दो दिन से नगर पालिका में काम काज ठप्प रहे। सुश्री भाचावत ने बताया कि कुछ भी घटनाक्रम हुआ हो लेकिन इस प्रकार सरकारी कर्मचारी से मारपीट करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और किसी को भी इस प्रकार की घटना का पक्षधर नहीं होना चाहिए। जबकि मारपीट करने वाला व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखता है। सुश्री भाचावत ने कहा कि पार्षद पति को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कौन सा मुद्दा या कौन सा विकास कार्य जनहित का था जो नपा कर्मचारी नही कर रहा था जिस पर पार्षद पति को इतना गुस्सा आ गया कि मारपीट तक करना पड़ी। सुश्री भाचावत ने बताया कि यदि नगर पालिका में अफसरशाही हावी है तो भाजपा के जनप्रतिनिधियों को अपने वरिष्ठ नेतृत्व को इससे अवगत कराना चाहिए न कि इस प्रकार मारपीट करना चाहिए। लगभग 20 से अधिक वर्षो से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी कभी किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने इस प्रकार की हरकत नहीं की। नगर पालिका में कुछ भी गलत हो रहा है तो सत्ता में बैठे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और सुधार करना चाहिए।

स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जी अरोरा स्मृति में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का ऐतिहासिक शुभारंभ

खिलाड़ियों का बौद्धिक स्तर देखकर हर कोई चकित

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कल गुरुवार को नीमच की धरती पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखा गया, नीमच की लाल माटी की धरती पर कल पहली बार अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सैकड़ों बच्चों की उपस्थिति और उनके अभिभावकों की गरिमामयी उपस्थिति में जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जी अरोरा की स्मृति में आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट का खेल प्रेमियों को बहुत समय से इंतजार था। कल 10:00 बजे ही जैसे ही प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ तो तालिया की गड़गड़ाहट से लायन डेन गूंज उठा। इस अवसर पर नीमच के गणमान्यजन जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह जी चौहान भईजी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सेठी, वरिष्ठ संपादक आरवी गोयल, पत्रकार राकेश सोन, पत्रकार दीपक खताबिया, कृषि मंडी के पूर्व अध्यक्ष उमराव सिंह जी गुर्जर की गरिमामयी उपस्थिति में समाजसेवी अशोक अरोरा की उपस्थिति में कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। सबसे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके पश्चात स्वर्गीय कश्मीरी लाल जी अरोरा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर सज्जन सिंह चौहान ने कहा कि

अरोरा परिवार का यह योगदान भुलाया नहीं जा सकता है उन्होंने नीमच के बच्चों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने के दरवाजे खोले हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

आरवी गोयल ने कहा कि अरोरा परिवार का शुरू से दान और धर्म से नाता रहा है लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन एक अच्छी शुरुआत है एक अच्छी पहल है और इसका स्कूली बच्चों और दूसरे शतरंज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बाहेती, सुरेंद्र सेठी, दीपक खताबिया, राकेश सोन और उमराव सिंह गुर्जर ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

प्रारंभ में सरस्वती पूजन के पश्चात डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयरत्न गर्ग व उनकी पूरी टीम व ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सोनी ने भी अतिथियों का माल्यार्पण कर पुष्प हारों से आत्मीय स्वागत किया। मंच पर उपस्थित समाजसेवी अशोक अरोरा ने भी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत कर कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

चूंकि बैडमिंटन की राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता का भी इसी के साथ संयुक्त उद्घाटन किया गया था इसलिए अतिथियों ने बैडमिंटन की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए भी शुभकामनाएं व्यक्त की। जिला बैडमिंटन संगठन के सचिव दीपक श्रीवास्तव विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित रहे।

मंच पर रखे दो-दो फीट के मोहरे आकर्षण का केंद्र बने - मंच पर विशेष रूप से बुलाए गए दो-दो फीट के बड़े-बड़े मोहरे रखे गए थे, जिनको देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो गया। अतिथियों व अशोक अरोरा ने मंच पर उपस्थित बच्चों के साथ इस बोर्ड पर खेल कर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विशेष बात यह रही कि इस अवसर पर सबसे कम उम्र के बालक साहिब सिंह गोत्र, नितेश ठाकुर ने भी चाल चली वहीं इसी प्रतियोगिता में सबसे बुजुर्ग अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी 85 वर्षीय आरके गुप्ता ने भी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर नए व युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

बच्चे हुए प्रसन्न- टूर्नामेंट स्थल पर अरोरा परिवार द्वारा बच्चों के खाने-पीने की चीजों की विशेष व्यवस्था की गई थी, बच्चे यहां का माहौल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जहां एक तरफ चाऊमीन, मंचूरियन व मसाला डोसा के स्टॉल लगे हुए थे वहीं दूसरी तरफ क्रिस्पी कॉर्न्स का स्वाद ले रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। गौरतलब है कि समाजसेवी अशोक अरोरा का बच्चों के प्रति विशेष लगाव है, यही वजह रही कि बच्चों के खाने-पीने व उनकी पसंद की चीजों का यहां पर हर राउंड के बाद बच्चों को तरह-तरह की व्यंजन परोसे गए। जिससे बच्चे दिन भर बहुत प्रसन्न दिखे।

व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही - लायन डेन में जहां बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया, वहीं युवा खिलाड़ियों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी खासी व्यवस्था की गई थी। बाहर से आए खिलाड़ियों ने भी यहां का माहौल देखकर खुशी जाहिर की। खिलाड़ियों ने तो यहां तक बोल दिया कि ऐसा टूर्नामेंट उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, जहां इतनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। यहां के लजीज व्यंजनों को देखकर उन्होंने यह बताया कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने आजतक नहीं देखी और पूरे दिन भर लुत्फ उठाया। शायद नीमच की धरती पर यह पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय आयोजन था जिसमें करीब पूरा शहर ही टूट पड़ा। सभी ने एक स्वर में मैनेजमेंट और यहां की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ की। कुल मिलाकर यह एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हुआ।

प्रथम दिन हुए चार राउंड- फीडे के शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम दिन चार राउंड हुए। जिसमें बच्चों और बड़ों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अब शुक्रवार को यानी आज 5 राउंड और खेले जाएंगे और उसके बाद शाम को 6:30 बजे पुरस्कार वितरण होगा।

फीडे के कड़े नियमों से हुआ प्रतियोगिता का आयोजन - अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के नियमों के अनुसार चल रहे इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शहर के लोगों व शतरंज के खिलाड़ियों ने पहली बार जाना कि फीडे के नियम कितने सख्त होते हैं। जहां फीडे के इस टूर्नामेंट में के ऑर्बिटर यशपाल अरोरा व उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट की कमान अपने हाथों में समान रखी थी। एक-एक बारीक बारीक चीज पर उनकी नजर बनी हुई थी। उन्होंने पूरी तरह फीडे के नियमों का पालन करते हुए इस टूर्नामेंट का संचालन किया और जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे थे उसे पर भी उन्होंने कड़े नियमों का प्रतिबंध लगाया। साथ ही उन्हें बताया कि यह संस्था किन नियमों के तहत यह काम करती है इससे खिलाड़ियों को व उनके अभिभावकों को भी अंतरराष्ट्रीय शतरंज के नियम सीखने को मिले।

सम्पादकीय

कानूनी सुधारों के बावजूद क्यों नहीं थमती हिंसा?

हर घंटे 51 महिलाएँ हिंसा का शिकार होती हैं। यह वाक्य किसी रिपोर्ट की पंक्ति भर नहीं, बल्कि समकालीन समाज के अंतर्मन से उठती पीड़ा की गूंज है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ लगभग 4.48 लाख मामले दर्ज हुए, यानी प्रतिदिन औसतन 1,227 एफआईआर। ये आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि हिंसा अपवाद नहीं, बल्कि एक भयावह सामान्यता बन चुकी है। घर की चारदीवारी, सड़कें, कार्यस्थल और अब डिजिटल दुनिया–कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा, और यही इस संकट की गंभीरता को और गहरा करता है।

हिंसा से भी अधिक चिंताजनक स्थिति तब बनती है, जब पीड़िता न्याय की चौखट पर पहुँचकर भी निराश लौटती है। बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि दर मात्र 22-28 प्रतिशत के आसपास रहना न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। एसिड अटैक जैसे अपराधों में दोषसिद्धि दर अत्यंत कम (कई वर्षों में 5-10 प्रतिशत से भी नीचे) है, जहाँ पीड़िता आजीवन शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलती है, जबकि अपराधी अक्सर कानून की खामियों का लाभ उठाकर बच निकलते हैं। यह स्थिति कानून के भय को कम और अपराधियों के हौसले को अधिक मजबूत करती है।

कम दोषसिद्धि दर के मूल में जांच और न्यायिक प्रक्रिया की खामियाँ गहराई से जुड़ी हैं। एफआईआर दर्ज करने में देरी, पुलिस की लापरवाही, वैज्ञानिक ढंग से सबूत न जुटा पाना और वर्षों तक लंबित रहने वाले मुकदमे न्याय को कमजोर बनाते हैं। गवाहों पर सामाजिक दबाव और डर उनकी गवाही को प्रभावित करता है, जिससे अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ जाता है। कई मामलों में पीड़िता को ही संदेह की नजर से देखा जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास टूटता है और वह न्याय की प्रक्रिया से दूर हो जाती है।

यह समस्या तब और विकराल हो जाती है जब इसमें जाति और वर्ग का आयाम जुड़ जाता है। दलित और आदिवासी महिलाओं के मामलों में दोषसिद्धि दर काफी कम (30-35 प्रतिशत के आसपास या उससे नीचे) रह जाना इस बात का संकेत है कि सामाजिक भेदभाव न्याय व्यवस्था के भीतर तक पैठ बना चुका है। कानून भले ही समान हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन समान नहीं है। पीड़िताओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक निर्भरता और सीमित संसाधन उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने से रोकते हैं, जिससे अपराधियों को एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।

घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे व्यापक और मौन रूप है। एनसीआरबी 2023 के अनुसार, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले कुल अपराधों का लगभग 30 प्रतिशत हैं। विडंबना यह है कि जिस घर को सुरक्षा का स्थान माना जाता है, वही कई महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बन जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 ने कानूनी संरक्षण का वादा किया था, परंतु इसके कमजोर क्रियान्वयन ने अपराधियों के भीतर भय पैदा नहीं किया। परिणामस्वरूप पीड़िताएँ चुप्पी में जीने को मजबूर रहती हैं।

इक्कीसवीं सदी में हिंसा का स्वरूप बदल रहा है और साइबर हिंसा एक नई चुनौती बनकर उभरी है। डीपफेक वीडियो, ऑनलाइन उत्पीड़न और रिवेंज पॉर्न महिलाओं की गरिमा और निजता पर सीधा हमला करते हैं। डिजिटल दुनिया में होने वाली हिंसा का प्रभाव वास्तविक जीवन में भी गहरा होता है, लेकिन कानून और जांच एजेंसियाँ अभी इस चुनौती से पूरी तरह निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। तकनीकी साक्ष्यों की समझ और त्वरित कार्रवाई के अभाव में अपराधी अक्सर बच निकलते हैं।

निर्भया कांड के बाद 2013 में किए गए आपराधिक कानून संशोधन ने समाज में उम्मीद जगाई थी। बलात्कार की परिभाषा का विस्तार हुआ, सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया और फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना हुई। इसके बाद वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और निर्भया फंड जैसे कदम उठाए गए। 2024 में लागू भारतीय न्याय संहिता ने डिजिटल सबूतों और कड़ी सजा पर जोर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर इन सुधारों का प्रभाव अपेक्षित गति से नहीं दिख पाया है।

दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए सबसे पहले जांच की गुणवत्ता में सुधार अनिवार्य है। फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीक का उपयोग और पुलिस बल की जेंडर संवेदीकरण ट्रेनिंग इस दिशा में निर्णायक कदम हो सकते हैं। गवाह संरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाकर उन्हें भयमुक्त वातावरण देना आवश्यक है। विशेष अभियोजकों की नियुक्ति और न्यायाधीशों के नियमित प्रशिक्षण से न्यायिक प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और संवेदनशील बन सकती है, जिससे पीड़िताओं का भरोसा लौटेगा।

कानूनी सुधार तब तक अधूरे हैं, जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती। स्कूलों से लेकर कार्यस्थलों तक लिंग समानता और संवेदनशीलता की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देने वाली व्यापक सामाजिक मुहिम की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें हिंसा से बाहर निकलने का साहस देता है, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपाय है।

कुछ राज्यों में बेहतर फोरेंसिक उपयोग और त्वरित जांच से दोषसिद्धि दर 40 प्रतिशत तक पहुँचना यह सिद्ध करता है कि सुधार संभव है। इन सफल मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। निर्भया फंड का पूर्ण उपयोग, प्रभावी वन-स्टॉप सेंटर और साइबर हिंसा के लिए अलग कानून समय की मांग हैं। अंततः महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकना और दोषसिद्धि दर बढ़ाना केवल कानून का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामूहिक संकल्प का प्रश्न है। जब तक अपराधियों को त्वरित और कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक एक सुरक्षित और समान भारत का सपना अधूरा रहेगा।

व्यक्ति में यह विवेक होना चाहिए कि वह एक शाश्वत अस्तित्व है : श्री माताजी

सहजयोग संस्थापिका श्री माताजी निर्मला देवी जी ने कुंडलिनी जागरण द्वारा मानव के समक्ष आत्मा व परमात्मा के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यह मार्ग सभी के लिए है बस आवश्यकता है बिना किसी पूर्वाग्रह व वाद - विवाद के इसका अनुभव प्राप्त करने की। सत्य यह कि हम सभी स्वयं को मात्र एक देह मानकर चलते हैं । हमारा संपूर्ण जीवन इस देह की संतुष्टि में ही प्रयासरत रहता है। हम ये जानने का प्रयास भी नहीं करते कि जब देह नहीं होगी तब हम क्या होंगे ? श्री माताजी ने अपनी अमृतवाणी में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि, ÷व्यक्ति को जीवन के बारे में अत्यंत विवेकशील और सूझबूझ वाला दृष्टिकोण रखना होगा, यह कि आप स्वयं शाश्वत जीवन हैं, यह कि आप स्वयं शाश्वत अस्तित्व हैं, और यह कि आप इस धरती पर परमात्मा के बनाए आशीर्वादों का आनंद लेने के लिए आए हैं, न कि रोने-धोने के लिए, चिल्लाने के लिए, और दोषी महसूस करने के लिए। यह आपका काम नहीं है। पहली चीज़ यह है कि यही विवेकशीलता है कि आपको छोटी-छोटी तुच्छ चीज़ों के लिए दुखी नहीं होना है चाहें आपके लिए जानें बिखरा हुआ है। अपने आप में आप एक अभिनव कंप्यूटर हैं और आपको केवल मुख्य स्त्रोत से जुड़ना है। लेकिन यह संदेश मिलने के बाद भी, वे इससे जुड़ना नहीं चाहते मगर यही एक चीज़ है जिसके लिए आप इस दुनिया में आये हैं। आप विकास प्रक्रिया में एक अमीबा से इस अवस्था तक पहुँचे हैं।एक माँ के स्वरूप में, मैं आपसे कहती हूँ कि यही आपका राज्याभिषेक है। आपके पिता स्वयं सारी शक्तियाँ प्रवाहित करने के लिए व्याकुल हैं, जो वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं। वह चाहते है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और आप इसे प्राप्त करें क्योंकि इसे प्राप्त करना आपका अधिकार है।

विकसित भारत के सारथीः प्रवासी भारतीय और 2047 का संकल्प

हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे एन आर आई दिवस(नोन-रेजिडेंट इंडियन डे) भी कहा जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि इस दिन को इसलिए चुना गया था, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गाँधी दक्षिण अफ़्रीका से भारत वापस आए थे, और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास की बात करें तो यह दिवस साल 2003 से मनाया जा रहा है, जब पहली बार भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मान देने के लिए इसे आयोजित किया।

यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स) द्वारा आयोजित होता है।प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्यों की यदि बात करें तो इसमें क्रमशः विश्व में बसे भारतीयों द्वारा भारत के विकास और समाज में दिए योगदान को सम्मानित करना, भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच सम्बन्धों को मज़बूत करना, एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ प्रवासी भारतीय अपनी राय, अनुभव और सुझाव साझा कर सकें तथा प्रवासी भारतीय सम्मान(अवार्ड) जैसे पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करना है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सम्मान है जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है, जो विदेश में रहते हुए भारत और भारतीय समुदाय के लिए विशिष्ट योगदान देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रवासी भारतीय दिवस के प्राथमिक लक्ष्य भारत और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण करना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में प्रवासी भारतीयों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है। साथ ही, यह विश्व समुदाय के बीच भारत की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करते हुए विदेशों में भारत के प्रति बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के समर्थन को बढ़ावा देता है और विश्वभर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रवासी भारतीयों को अपनी पैतृक भूमि की सरकार और जनता से भावनात्मक व वैचारिक रूप से जुड़ने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है, जिससे पारस्परिक सहयोग और विश्वास और अधिक मजबूत होता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि साल 2003 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और उसके बाद अन्य शहरों में भी पारंपरिक रूप से इसका आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने एवं उनके साथ जुड़ने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2015 में इसे दो साल में एक बार आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक दो साल में 9 जनवरी को मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) एक उल्लेखनीय आयोजन है जिसके तहत भारतीय प्रवासियों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिये दिये गए योगदान पर प्रकाश डाला जाता है।पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम- विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रखी गई थी तथा इसका आयोजन ओडिशा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया गया था।इस साल 9 जनवरी 2026 को सांकेतिक रूप से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए यह आलेख लिखे जाने तक किसी विशेष थीम की आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई है।

बहरहाल, यदि हम यहां पर प्रवासी भारतीयों के योगदान की बात करें तो प्रवासी भारतीय विकसित भारत के निर्माण में आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक सेतु के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। वे न केवल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजकर अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और स्टार्टअप फंडिंग के माध्यम से नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में अर्जित अपने तकनीकी ज्ञान और अनुभव (ब्रेन गेन) को भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा करके वे कौशल विकास(स्किल डेवलपमेंट) में भी मदद कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने और भारतीय उत्पादों के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार तैयार करने में भी उनकी भूमिका निर्णायक है। अंततः, अपनी मातृभूमि के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव और वैश्विक नेटवर्किंग भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की गति को तेज कर सकती है।

हालांकि,प्रवासी भारतीयों से संबंधित अनेक चुनौतियां भी विद्यमान हैं।मसलन,प्रवासी भारतीयों से संबंधित चुनौतियों को संक्षेप में देखें तो प्रमुख समस्या प्रशासनिक जटिलता और कानूनी बाधाओं की है, जहाँ भारत में निवेश या संपत्ति प्रबंधन के दौरान उन्हें लालफीताशाही और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कई देशों में प्रवासियों को नस्लभेद, कार्यस्थल पर असुरक्षा और कड़े वीजा नियमों जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। दूसरी ओर, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान न होना भी प्रवासियों की नई पीढ़ी को पूरी तरह जुड़ने से रोकता है। बहरहाल, यहां जानकारी देना चाहूंगा कि प्रवासी भारतीयों की सहायता और उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने दो मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मदद पोर्टल तथा ई-माइग्रेट पोर्टल तैयार किए हैं।मदद पोर्टल की बात करें तो यह विदेश मंत्रालय की एक प्रभावी ऑनलाइन समाधान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों की आपातकालीन शिकायतों का निवारण करना है। यदि किसी प्रवासी भारतीय को विदेश में कानूनी समस्या, पासपोर्ट खोने, घरेलू उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है, तो वे इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि शिकायतों की निगरानी सीधे उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है और समाधान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है। वहीं दूसरी ओर ई-माइग्रेट पोर्टल मुख्य रूप से उन भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है जो रोजगार के लिए विदेश (विशेषकर खाड़ी देशों) जाते हैं। यह विदेशी नियोक्ताओं और भर्ती एजेंटों के डेटाबेस को एकीकृत करता है, जिससे श्रमिकों को फर्जी एजेंटों और शोषण से बचाया जा सके। इसके माध्यम से श्रमिक अपनी बीमा पॉलिसी (प्रवासी भारतीय बीमा योजना) और अपने रोजगार अनुबंध की वैधता की जांच आसानी से कर सकते हैं।आगे की राह के रूप में, भारत को प्रवासियों के लिए सिंगल विंडो डिजिटल सिस्टम और विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनके संपत्ति विवाद जल्द सुलझ सकें। साथ ही, नमन जैसे पोर्टल्स के जरिए उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण और नो इंडिया प्रोग्राम जैसे सांस्कृतिक अभियानों के माध्यम से युवा पीढ़ी को जड़ों से जोड़ना आवश्यक है। सरकार को वैश्विक स्तर पर उनके अधिकारों के लिए सक्रिय कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वे बिना किसी भय के विकसित भारत के विजन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। निष्कर्षतः, हम यह बात कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय और उनकी मातृभूमि के बीच के गहरे भावनात्मक और रणनीतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का एक सशक्त मंच है। यह दिवस प्रवासियों की उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ-साथ उन्हें विकसित भारत 2047 के संकल्प में सक्रिय भागीदार बनाने का अवसर प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय अपनी पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता और वैश्विक प्रभाव के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक जीवंत सेतु (लिविंग ब्रिज) का कार्य कर रहे हैं। अंततः, उनकी सक्रिय सहभागिता ही भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कुंजी है।

-सुनील कुमार महला

भारत-अमेरिका समझौते में क्यों हो रही देरी?

भारत और अमेरिका दोनों ने अन्य देशों के साथ शीघ्र समझौतों पर हस्ताक्षर किए लेकिन वे आपस में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सके? बीते चार साल में भारत ने आठ व्यापार समझौते किए हैं। ये समझौते मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ब्रिटेन और हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) के सदस्यों के साथ किए गए हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने भी विगत छह महीनों में जापान, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में भारत-अमेरिका समझौते में इतना समय क्यों लग रहा है?

दो मुख्य वजहें- पहली वजह, अधिकांश देश जिन्होंने अमेरिका के साथ शीघ्र व्यापार समझौते किए हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारत की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, अमेरिका-भारत व्यापार समझौता व्यापार से परे सामरिक और नीतिगत क्षेत्रों तक विस्तृत है।

ये दो कारण वार्ताओं को जटिल बनाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि आखिर क्यों समझौता कई लोगों की उम्मीद से अधिक वक्त ले रहा है।

सुरक्षा प्रदाता के रूप में अमेरिका- अमेरिका के साथ शीघ्रता से व्यापार समझौते करने वाले देशों में एक समानता है। वे सभी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के औपचारिक संधि साझेदार हैं और उनके यहां बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं। अमेरिका के साथ उनके व्यापारिक संबंध सुरक्षा पर निर्भरता से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर उत्तर कोरिया और चीन के खतरों को देखते हुए।

यूरोप में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ब्रिटेन नॉटो के जरिये अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। यूरोपीय संघ का बड़ा हिस्सा, खासतौर पर रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद काफी हद तक अमेरिकी सेना की मदद पर निर्भर है। ऐसे मामलों में व्यापार वार्ताएं रणनीतिक पहलू से तय होती हैं। ऐसे में अमेरिकी मांगों के आगे झुकना एक तरह की मजबूरी है। दक्षिण पूर्व एशिया में भी हालात ऐसे ही हैं। फिलिपींस साझा रक्षा संधि से बंधा हुआ है। हाल के वर्षों में उसके यहां अमेरिकी सेना की पहुंच बढ़ी है। थाईलैंड एक अन्य साझेदार है जो अमेरिकी सुरक्षा ढांचे से बंधा है। इन देशों के लिए व्यापार समझौते व्यापक भू-राजनीतिक मोलभाव का हिस्सा हैं जिसकी जड़ें सुरक्षा निर्भरता में निहित हैं।

दूसरी तरफ, भारत अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है और सैन्य दबाव के माध्यम से उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता।

-धनंजय राजौरा

भूख से मुक्ति का राष्ट्रीय संकल्प है अटल कैंटीन योजना

भूख केवल एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, वह सामाजिक असंतुलन, मानसिक कुंठा और नैतिक विचलन की जननी भी है। इतिहास साक्षी है कि जब पेट खाली होता है, तो विचार उग्र हो जाते हैं, व्यवस्था के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है और विद्रोह की भावना पनपती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि उसका कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इसी बुनियादी और मानवीय सोच के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा शुरू की गई रुपये 5 में भोजन उपलब्ध कराने की 'अटल कैंटीन योजना' निस्संदेह एक दूरदर्शी, करुणामय, मानवीय और जनकल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और मानवीय है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राजधानी जैसे महानगर में, जहाँ एक ओर समृद्धि और चमक-दमक है, वहीं दूसरी ओर असंगठित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शाचालक, ठेला-पटरी वाले, घरेलू कामगार और बेघर लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इनके लिए दो वक्त का सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन आज भी एक चुनौती बना हुआ है। अटल कैंटीन योजना इन्हीं वर्गों के लिए जीवनरेखा बनकर सामने आई है, जो 'संकल्प से सिद्धि' के लक्ष्य को दर्शाता है और इसे देश में भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस योजना का शुभारंभ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर किया जाना केवल एक औपचारिक तिथि चयन नहीं, बल्कि एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक है। अटलजी का संपूर्ण राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के विचार से प्रेरित रहा। वर्ष 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अटलजी के लिए गरीब केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि नीति का केंद्र था। उस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया गया, जिससे करोड़ों लोगों को भुखमरी से राहत मिली। अटल कैंटीन योजना उसी सोच का आधुनिक शहरी संस्करण है, जहाँ अनाज के बजाय तैयार, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन सीधे थाली में परोसा जा रहा है। यह नीतिगत निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि सुशासन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील क्रियान्वयन से साकार होता है। अटल कैंटीन में भोजन की कीमत रुपये 5 रखी गई है, जबकि सरकार प्रत्येक थाली पर रुपये 25 की सब्सिडी दे रही है। यह मूल्य निर्धारण अत्यंत सोच-समझकर किया गया है। भोजन पूरी तरह मुफ्त न देकर एक न्यूनतम राशि तय करने का उद्देश्य यह है कि भोजन की कद्र बनी रहे और लाभार्थी इसे भीख नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान के रूप में ग्रहण करे। यह नीति सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

रेखा गुप्ता सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए जिस संवेदनशीलता, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है, वह उनके प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व को रेखांकित करता है; अटल कैंटीन जैसी योजनाएँ बताती हैं कि वे शासन को सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम मानती हैं।

किंतु सर्दी के इस कठोर मौसम में दिल्ली की सड़कों, फुटपाथों और फ्लाईओवरों के नीचे ठिठुरती रातें काटने को विवश गरीब और बेघर लोगों के लिए केवल मौसमी रैन-बसेरे पर्याप्त नहीं हैं, आवश्यकता एक स्थायी, समन्वित और मानवीय शीत-रक्षा योजना की है, जिसमें अस्थायी आश्रय के साथ गरम वस्त्र, पौष्टिक भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था हो, ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की सड़कों पर कोई भी व्यक्ति सर्द रात में बेसहारा और अदृश्य न रहे; ऐसा कदम न केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता का प्रमाण होगा, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक जिम्मेदारी का भी सशक्त निर्वाह बनेगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उपलब्ध कराया जा रहा भोजन पोषण मानकों के अनुरूप है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई मानकों का पालन किया जाता है, जिसमें प्रति थाली 700-800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है। डिजिटल टोकन, सीसीटीवी और निगरानी के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक कैंटीन प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता रखी है, और 100 कैंटीन खोलने का लक्ष्य है। दाल, सब्जी, रोटी/चावल जैसे संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आरओ वाटर एवं अचार आदि भी परोसा जा रहा है ताकि यह योजना केवल पेट भरने तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य सुधार में भी योगदान दे सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और निम्न आय वर्ग के लिए मुफ्त एवं रियायती अनाज योजनाएँ लगातार संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहलों ने संकट काल में करोड़ों परिवारों को राहत दी है। इन योजनाओं का मूल दर्शन यही है कि भूखा नागरिक न आत्मनिर्भर बन सकता है और न ही राष्ट्रनिर्माण में भागीदार। रेखा गुप्ता सरकार की अटल कैंटीन योजना इन राष्ट्रीय प्रयासों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य, यदि समान मानवीय दृष्टि से काम करें, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से संभव है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भुखमरी और अपराध के बीच गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो वह व्यवस्था के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण अपनाने लगता है। यही कारण है कि अनेक महान नेताओं ने यह कहा है कि गरीब को पहले रोटी दो, उपदेश बाद में।

भूखे को खिलाना किसी प्रकार का राजनीतिक प्रलोभन नहीं है। यह सच्ची राष्ट्रभक्ति, मानवीय कर्तव्य और सामाजिक सुरक्षा का आधार है। अटल कैंटीन जैसी योजनाएँ अपराध को नियंत्रित करने, सामाजिक असंतोष को कम करने और लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करने का कार्य करती हैं। हालाँकि, किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता केवल उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि उसके पारदर्शी, निगरानी और ईमानदार क्रियान्वयन से तय होती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि अटल कैंटीन योजना को भ्रष्टाचार, अपव्यय और लापरवाही से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। खाद्य सामग्री की खरीद, भोजन की गुणवत्ता, लाभार्थियों की पहुँच, वित्तीय प्रबंधन और संचालन व्यवस्था-हर स्तर पर सख्त निगरानी, नियमित ऑडिट और सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि इस योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रवेश करता है, तो वह न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, बल्कि गरीब के विश्वास के साथ भी विश्वासघात होगा।

दिल्ली की यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती है। शहरीकरण के इस दौर में लगभग हर बड़े शहर में श्रमिक और निम्न आय वर्ग भोजन संकट से जूझ रहा है। यदि प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार ऐसी योजनाएँ विकसित करे, तो देश से भुखमरी को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि ऐसी योजनाएँ खर्च नहीं, बल्कि सामाजिक निवेश हैं। यह निवेश समाज को स्थिरता, शांति और विश्वास लौटाता है।

अंततः रुपये 5 की थाली केवल भोजन नहीं है। यह करुणा, गरिमा और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्योदय सोच और नरेन्द्र मोदी के वर्तमान नेतृत्व की मानवीय दृष्टि का सार्थक संगम है। रेखा गुप्ता सरकार की यह पहल यह संदेश देती है कि सुशासन वही है, जो सबसे पहले सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुँचे। यदि इस योजना को पारदर्शिता, ईमानदारी और निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया गया, तो यह न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश के लिए भूख-मुक्त भारत की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध होगी।

-ललित गर्ग

वैश्विक विश्व युद्ध के मुहानें पर बैठी मानवता

सावधान ? मानवीय जीवन आज परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ा है और पूरी पृथ्वी जैसे किसी सक्रिय ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि अगला सनकी आदेश किस राजधानी से निकलेगा। परमाणु संपन्न देशों के शासक स्वयं को वैश्विक सिरमौर सिद्ध करने की खतरनाक होड़ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, विस्तारवादी मंसूबों और व्यक्तिगत सनकों को मानवता के अस्तित्व से ऊपर रख चुके हैं।

चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश जहाँ परमाणु शक्ति तानाशाही प्रवृत्तियों के हाथों में केंद्रित है। वहाँ यह खतरा और भी भयावह हो जाता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब सत्ता विवेक से कट जाती है तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम आज भी मानवता के माथे पर कलंक की तरह दर्ज हैं। उसे समय के परमाणु हमले के विकिरण के दुष्प्रभाव आज भी जापान के बच्चों के शरीर और भविष्य में देखे जा सकते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन द्वारा 2022 के बाद से सौ से अधिक हथियारों के परीक्षण जिनमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को लक्ष्य करने वाली परमाणु मिसाइलें शामिल हैं। यही इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि यह देश किसी भी क्षण सनक में विनाशकारी कदम उठा सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते बल्कि वैश्विक संतुलन को झकझोर कर रखा देते हैं और यूक्रेन को नाटो तथा अमेरिका से मिल रही सहायता के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी दे चुके हैं ।जबकि उन्हें यह अनुमान ही नहीं था कि यूक्रेन इतना लंबा प्रतिरोध कर पाएगा, चीन और ताइवान विवाद में भी अमेरिका के परोक्ष हस्तक्षेप से नाराज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र युद्ध के केंद्र में आ सकता है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक विरोधी बन चुके हैं और अमेरिका स्वयं को विश्व का सर्वशक्तिमान बनाए रखने के दबाव में लगातार युद्धोन्मुखी नीति अपनाए हुए है।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया की सीमा पर लगातार सैन्य अभ्यास को प्योंगयांग हमले के पूर्वाभ्यास के रूप में देख रहा है।जबकि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय समझौतों के तहत संयुक्त बैलिस्टिक मिसाइल रणनीति पर आगे बढ़ चुके हैं।, इन तैयारियों के जवाब में उत्तर कोरिया द्वारा रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षणों का निरीक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि टकराव की जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी है। पश्चिम एशिया में वेनेजुएला संकट, इसराइल-फिलिस्तीन युद्ध और यूक्रेन संघर्ष आपस में जुड़कर एक ऐसे वैश्विक युद्ध की प्रस्तावना रच रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और खाड़ी देशों की भागीदारी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में चुनावी दबावों के चलते वहां का नेतृत्व अपनी वैश्विक बादशाहत बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार दिखाई देता है और उसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल जैसे देश आंख मूंदकर खड़े रहते हैं।भारत की स्थिति इन परिस्थितियों में अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि एक ओर उसकी चीन से परंपरागत शत्रुता है तो दूसरी ओर रूस से गहरे रणनीतिक संबंध और अमेरिका से बढ़ती निकटता है जबकि भारत लगातार शांति और संतुलन की भूमिका निभाने का प्रयास करता रहा है। परंतु जब विश्व की प्रमुख शक्तियां ही संवाद की बजाय दंभ और हथियारों की भाषा बोलने लगें तो किसी भी क्षण चिंगारी विश्वयुद्ध में बदल सकती है और यदि ऐसा हुआ तो यह युद्ध केवल देशों का नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता और पृथ्वी के अस्तित्व का युद्ध होगा, ऐसे समय में विश्व को नेताओं की सनक नहीं बल्कि विवेक की आवश्यकता है और मानवता के पास अब केवल यही एक प्रार्थना शेष रह जाती है कि युद्ध नहीं हो और शांति ही अंतिम विकल्प बने।

-संजीव ठाकुर

सिविल लाइंस के आवासीय भूखंड को व्यवसायिक करने पर स्वामियों को निगम ने किया नोटिस जारी

मामला आवासीय भूखंड पर दुकानें बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने का

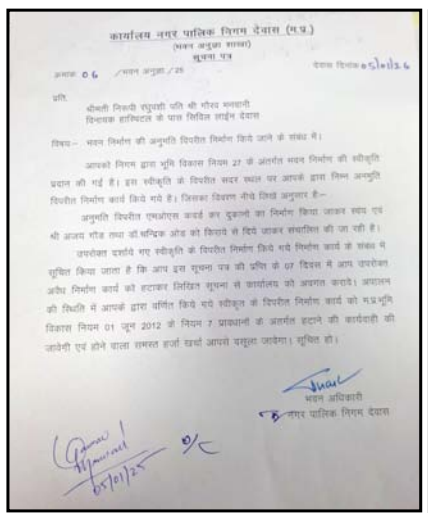

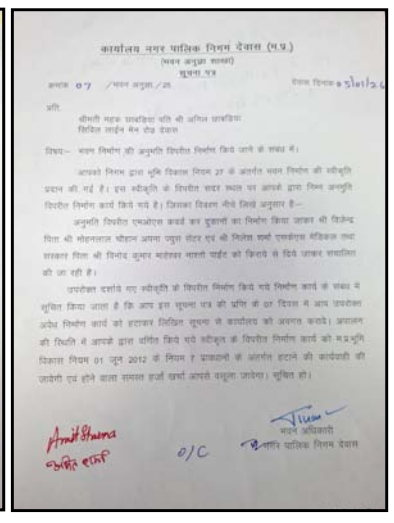

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में प्राधिकरण के बने भवनों के सामने मुख्य मार्ग पर एमओएस पर भूखंड स्वामियों द्वारा अवैध निर्माण करते हुए टीन शेड की दुकानें बनाकर व्यावसायिक उपयोग की दुकानें किराये पर चढ़ा दी गई थी। इस मामले को लेकर दैनिक मालवा हेराल्ड ने लगातार समाचार प्रकाशित कर नगर निगम का ध्यान इस ओरआकर्षित किया था।

खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम उपायुक्त देव बाला पिपलोनिया ने मामले को संज्ञान में लिया और क्षेत्रीय इंजीनियर विजय जाधव को उक्त क्षेत्र में सर्वे कर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। क्षेत्रीय इंजीनियर जाधव ने इस मामले में सर्वे कर अपनी रिपोर्ट नगर निगम उपायुक्त पिपलोनिया को सौंपी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आवासीय भूखंड पर अवैध निर्माण कर भूखंड स्वामियों द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु दुकानें किराये पर चढ़ा दी गई हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद नगर निगम ने इस मामले में भूखंड स्वामियों को सूचना पत्र जारी किए हैं और इस सूचना पत्र में एक सप्ताह में पूरी जानकारी नगर निगम को प्रेषित करने को कहा है। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि यदि सात दिवस के अंदर संतोष प्रद जवाब नहीं दिया जाता है तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।

सूचना पत्र मिलने के बाद भूखंड स्वामियों में हड़कंप मच गया है और वे सभी तरह के जतन करने में जुट गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। अब उन्हें बुलडोजर की कार्रवाई का डर सताने लगा है। कारण यह है कि इन अवैध निर्माणों के चलते वे दुकानें किराये पर चढ़ाकर प्रतिमाह मोटी रकम वसूला करते थे। अब उन्हें प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपए का नुकसान नजर आने लगा है। वहीं अवैध निर्माण टूटने से होने वाले नुकसान का भी भय सता रहा है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से सिविल लाइंस क्षेत्र में ऐसी दुकानें संचालित हो रही हैं, जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। जबकि इस क्षेत्र में अधिकतर प्रशासनिक अधिकारियों के निवासी हैं और उनका अक्सर इस मार्ग से आना-जाना लगा रहता है। बावजूद इसके यह दुकानें बिना किसी डर के संचलित हो रही थीं। कहीं न कहीं इसमें मिलीभगत की बू भी आने लगी थी। लेकिन जब दैनिक मालवा हेराल्ड ने इस मामले को उजागर किया तो नगर निगम को इस ओर ध्यान देना पड़ा और अब सूचना पत्र जारी किए गए हैं। पिछले कुछ समय से नगर निगम का अमला एमजी रोड पर अतिक्रमण हटाने में लगा हुआ था। अब वहां विकास कार्य की शुरुआत हो चुकी है। अब लगता है, एक सप्ताह में नगर निगम का यह अमला सिविल लाइंस क्षेत्र का रुख करेगा। ताकि इन अवैध निर्माणों को तोड़ा जा सके। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि सिविल लाइंस क्षेत्र में ही कुछ प्रायवेट नर्सिंग होम भी संचालित हो रहे हैं, जिनके पिछले हिस्से के भवन आवासीय क्षेत्र में निर्मित हैं, लेकिन इन भवनों के कमरे भी मरीजों को भर्ती करने के लिए व्यावसायिक उपयोग में लिए जा रहे हैं। अभी तो नगर निगम ने अवैध निर्माण की दुकानों को ही सूचना पत्र जारी किए हैं। निकट भविष्य में इन नर्सिंग होम संचालकों की बारी भी आ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो नगर निगम को न सिर्फ राजस्व की बढ़ोतरी होगी, बल्कि अवैध निर्माण पर भी अंकुश लगेगा। अब देखना यह है कि नगर निगम सूचना पत्र में दी गई अवधि के बाद क्या कार्रवाई करता है ?

नई बनने के बाद पुरानी को करेंगे डिस्मेंटल

पुरानी टंकी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब, अब सीधे पहुंचाया जाएगा पानी

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर के भागीरथपुरा में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका द्वारा भी नगर में किए जाने वाले जन वितरण को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। नगर में बनी पुरानी टंकियों की सफाई कराने के बजाए अब इसे डिस्मेंटल कर दिया जाएगा और नई बनकर तैयार टंकी से शुद्ध पानी नगर में वितरण किया जाएगा ताकि नगर में ऐसे हालात न बने।

दरअसल नगर पालिका कार्यालय के समीप पानी की टंकी का निर्माण कार्य जारी हैं। बताया जाता है कि इस पानी की टंकी का निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद जिला अस्पताल के समीप स्थित पानी की पुरानी टंकी को डिस्मेंटल किया जाएगा। क्योंकि ये टंकी काफी पुरानी होकर जर्जर होने लगी हैं। वहीं इसकी सफाई भी नहीं हो पाती हैं। इससे ये टंकी परेशानी बन सकती हैं। इस कारण नपा द्वारा इसे डिस्मेंटल किया जाएगा।

बाहर की टीम से करवाई जाएगी टंकियों की सफाई- नगर में चीलर डैम से पाइप लाइन के माध्यम से पानी को जल शुद्धिकरण केंद्र तक पहुंचाया जाता हैं। यहां से पानी को फिल्टर करके नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में बनी हुई पानी की टंकियों तक पहुंचाया जाता हैं। इन टंकियों के भरने के बाद नगरवासियों को पेयजल का वितरण किया जाता हैं। ऐसे में इन पानी की टंकियों की निश्चित समय अंतराल पर सफाई कराई जाती हैं। नगर में पानी की टंकियों की सफाई के लिए बाहर से टीम को बुलवाया जाता हैं। क्योंकि पूर्व में किला परिसर में स्थित पानी की टंकी की सफाई करने के लिए इसमें उतरे एक कर्मचारी की टंकी में फंसने से मौत हो गई थी। इसके बाद टंकियों की सफाई के लिए विशेषज्ञों को बाहर से बुलवाया जाता हैं। जिससे सावधानीपूर्वक टंकियों की सफाई हो सके। ऐसे में अब नगर पालिका द्वारा बाहर से टीम को बुलवाया जा रहा हैं। टीम के आने पर टंकियों की सफाई कराई जाएगी।

जर्जर टंकी के बजाए सीधे करेंगे पानी सप्लाई- जिला अस्पताल के समीप स्थित पुरानी पानी की टंकी में भी पानी को चढ़ाकर सप्लाई किया जाता हैं। ऐसे में लंबे समय से इस टंकी की सफाई नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि टंकी की हालत जर्जर हो रही हैं। ऐसे में इस टंकी से सप्लाई किए जाने वाले पानी में भी खराबी आ सकती हैं। हालांकि नपा का कहना है कि यदि इस टंकी के पानी में परेशानी आई तो इसमें पानी चढ़ाने की बजाय पानी को सीधे सप्लाई किया जाएगा।

इनका कहना है- अस्पताल के पास वाली पानी की टंकी सफाई आवश्यक है, लेकिन इसके अंदर उतरकर इसे साफ नहीं किया जा सकता हैं। क्योंकि ये टंकी जर्जर हो रही हैं। नगर पालिका के पास वाली टंकी बन जाएगी तो फिर इस पुरानी टंकी को डिस्मेंटल कर देंगे। ऐसे में अभी इस टंकी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि टंकी से खराब पानी आता है तो इसमें पानी चढ़ाने की बजाय सीधे सप्लाई करेंगे। नगर की सभी सभी टंकियों की सफाई फिर से कराई जाएगी। इसके लिए बाहर से टीम को बुलवाया गया हैं।

- भूपेंद्र दीक्षित, सीएमओ, नगर पालिका-शाजापुर

हाथों में पताका और वाहनों पर सवार होकर निकले सनातनी वीर...

विशाल वाहन रैली ने जगाई हिंदू सम्मेलन की अलख

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। हाथों में भगवा पताकाएं और होंठों पर जय श्री राम का गगनभेदी जय घोष करते हुए जब सनातनी वीरों की सैना 100 से अधिक दुपहिया वाहनों पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकली तो क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण हिंदुत्व के सनातनी रंग में सराबोर हो गया।

अवसर था संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त नगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन के अंतर्गत महाराणा प्रताप बस्ती की वाहन रैली का। इस संबंध में श्री संकट मोचन हनुमान हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति सहसंयोजक मंगल नाहर ने बताया कि दिनांक 10 जनवरी शनिवार को महाराणा प्रताप बस्ती के हिंदू सम्मेलन का आयोजन टंकी चौराहा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में दोपहर 2.30 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम की अलख जगाने तथा क्षेत्र के अधिक से अधिक हिंदू परिवारों के आयोजन में सहभागिता का आवाह्न करने हेतु दिनांक 8 जनवरी गुरुवार को शाम 4.30 बजे सनातनी वीरों द्वारा बस्ती में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। उक्त वाहन रैली स्थानीय काली माता मंदिर स्टेशन रोड़ से प्रारंभ होकर बस्ती के विभिन्न प्रमुख मार्गो आदर्श कालोनी, टंकी चौराहा, गैस गोडाउन, औद्योगिक क्षेत्र, बेरछा रोड़, अयोध्या बस्ती, खाटू श्याम मंदिर, तालाब डेरा मार्ग, कांजा मार्ग, नीलकंठ कालोनी, नहर मार्ग, कृष्णा कालोनी, एबी रोड़, शिक्षक कालोनी तथा पुनः नहर मार्ग से होती हुई काली माता मंदिर स्टेशन रोड़ पहुंचकर संपन्न हुई। उक्त रैली में बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवा तथा पुरुष वर्ग ने सम्मिलित होकर आयोजन को सफल बनाया। अंत में काली माता मंदिर में भारत माता की आरती के साथ आयोजन का समापन किया गया।

भव्य कलश यात्रा का कल होगा आयोजन- कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत मुख्य आयोजन दिवस दिनांक 10 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे से स्टेशन रोड़ स्थित कृष्णा कालोनी के समीप से मातृशक्ति की भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। उक्त कलश यात्रा धोबी चौराहा टंकी चौराहा होते हुए मुख्य समारोह स्थल पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति के शामिल होने का आह्वान समस्त समिति पदाधिकारियों ने किया है।

बकाया राशि जमा नही, कुर्की की कार्यवाही मे की तालाबंदी, गार्डन हुआ सील

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। निगम राजस्व विभाग की टीम के द्वारा निगम संपत्तिकर के बकायादारों के विरूद्ध सख्ती से कुर्की की कार्यवाही करते हुये राशि वसुली जा रही है। आयुक्त दलीप कुमार के निर्देशन मे राजस्व टीम द्वारा बकायादारों, गार्डनों एवं व्यवसाईक दुकानों, प्रतिष्ठानों पर तालबंदी की कार्यवाही मे बीमा रोड पर स्थित गेलेक्सी गार्डन पर संपत्तिकर की राशि 15 लाख व कचरा संग्रहण शुल्क की राशि 34 हजार 3 सौ 85 पर कुर्की की कार्यवाही करते हुये तालाबंदी की गई।

गार्डन भू स्वामी नही दिखा पा रहा है दस्तावेज, गार्डन होगा सील- इसी प्रकार बीमा रोड पर स्थित कबीर मैरिज गार्डन का मौका निरीक्षण पर चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत नही रकने तथा निगम राजस्व मे उक्त गार्डन को रेकार्ड दर्ज नही होने पर 3 दिवस मे दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौके पर सूचना पत्र दिया। उपायुक्त पटेल ने बताया कि संबंधित के द्वारा 3 दिवस मे दस्तावेज प्रस्तुत नही करते हैं तो गार्डन को सील करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

प्रतिदिन होगी कुर्की की कार्यवाही- उपायुक्त श्री पटेल ने बताया कि अन्य वार्डो मे कुर्की की कार्यवाही के दौरान वार्ड 35 मे कैदारसिंह पर 41 हजार 5 सौ 85, हिमरतसिहं पर 35 हजार 2 सौ 45, दौलतसिंह पर 41 हजार 3 सौ 64, वार्ड 38 मे ओमप्रकाश बालकिशन भूतडा पर 59 हजार 8 सौ 45 की संपत्तिकर की राशि बकाया होने पर करदाताओं के द्वारा राशि जमा कराई गई।

विच्छेद होगें नल कनेक्शन, सप्लाय भी किया बंद- वार्ड 33 मे अशोक पिता बाबुलाल कुमावत, प्रमोद रमेश शर्मा, लखन बाबुलाल पटेल, अमरजीत कौर कुलवंतसिंह पर संपत्तिकर की राशि बकाया होने पर 7 दिवस मे कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से मिली राहत, बढ़ने लगा तापमान

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के मौसम में अब बदलाव होने लगा है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का दंश झेल चुके नगरवासियों को अब सर्दी से राहत मिलने लगी है। दिन में धूप खिलने के साथ ही तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी।

इसके पहले नगर में सुबह से शाम तक सर्द हवाएं चलने के साथ ही आसमान पर घना कोहरा छाया हुआ था। दो दिन पहले तापमान भी 4 डिग्री तक पहुंच गया था। जिससे लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। इसके बाद तापमान बढ़ने लगा। गुरूवार को नगर का अधिकतम तापमान 25.6 व न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सुबह से ही आसमान साफ होने से तेज धूप भी खिली हुई थी जिससे दिन में लोगों के पसीने छूटने लगे। मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया ने बताया कि आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिन में गर्मी से राहत रहेगी, लेकिन शाम और सुबह सर्दी का असर रहेगा। जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा।

आसमान साफ होने से धूप खिलने लगी है, लेकिन अभी भी नगर में हल्का कोहरा छा रहा है। गुरूवार सुबह भी आसमान पर कोहरे का पहरा था जिससे लोगों को ठिठुरने लगा। इसके बाद धूप खिलने से लोगों ने सर्दी से राहत महसूस की, लेकिन शाम को सर्द हवाओं के डेरा डालने से लोगों को सर्दी से ठिठुरना पड़ा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार कुछ दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा।

उनके सत्कर्मों को नहीं भूले जिलेवासी: श्री सिंह

नगरवासियों ने 76वी जयंती पर निराश्रितों को कराया भोजन

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। पूर्व गुलाना विधायक व सहकारिता के पितृ पुरूष स्व. मनोहर सिंह की 76वी जयंती पर उनके पुत्र समाजसेवी योगेंद्रसिंह बंटी बना के नेतृत्व में आयोजित किया गया। जहां श्री सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए निराश्रितों को भोजन कराया गया। रविवार को कार्यक्रम की शुरूआत में सभी ने श्री सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इसके बाद सभी ने निराश्रितों को भोजन वितरित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनके सुपुत्र योगेंद्रसिंह बंटी बना ने कहा कि मेरे पिताजी ने हर समय जरूरत मंदों की मदद की। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में वो स्थान पाया है जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाता रहूंगा ताकि मेरे पिता की स्मृति हमेशा जिलेवासियों के जहन में रहे। वरिष्ठ समाजसेवी वीरेंद्र व्यास ने कहा कि मनोहर सिंह जी बैंक चेयरमेन के पद पर थे। उस समय उन्होंने कभी न दिन देखा न रात बस हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। आज जिले में उनकी याद में कई जगह आयोजन हो रहे हैं जो दर्शाता है कि श्री सिंह भले ही हमारे बीच में न हो लेकिन उनके सत्कर्मों ने उन्हें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट, आशुतोष शर्मा, महेश बराड़ा, राजेश पायलेट, राजीव दुबे, विनीत वाजपाई, सत्या वात्रे, राजेश पारछे, लक्ष्मण गवली, वीरेंद्रसिंह गोहिल, सीताराम रवैया, अंकित आचार्य, शब्बीर भाई, शैलेन्द्र पायलेट, धर्मेन्द्रसिंह सिसौदिया, हेमंत आर्य, पं. गोविंद शर्मा, लकी बना, विजेंद्र पाटीदार, हेमंत शर्मा, राहुल मालवीय, आजाद भाई आदि उपस्थित थे।

मैजिक-बोलेरो की टक्कर, 2 घायल

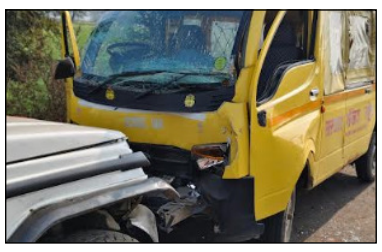

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोल्टा कालोनी के पास गुरुवार सुबह करीब 10 बजे एक मैजिक वाहन और बोलेरो के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो में सवार चार लोग मामूली घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही सुनेरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। डायल 112 की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया गया। घायलों में रिछोदा निवासी गिरवर सिंह (45) पिता गंगाराम और पुरुषोत्तम पिता हरिनारायण शामिल हैं। दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उनका उपचार शाजापुर जिला अस्पताल में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया जाता है कि बोलेरो वाहन में सवार लोग अपने निजी कार्य से बाटखेड़ी से रिछोदा की ओर जा रहे थे। तभी रांग साइड से आ रही मैजिक ने उसे टक्कर मार दी। जिस मैजिक वाहन से हादसे हुई, उस पर श्संस्कार पब्लिक स्कूल लिखा हुआ था। हादसे के समय मैजिक वाहन खाली था और उसमें कोई सवारी मौजूद नहीं थी। सुनेरा थाना प्रभारी अंकित मुकाती ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर भेजा गया था। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर किनारे खड़ा करवा दिया गया है, जिससे यातायात सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत नहीं की है।

योजना सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कांग्रेस को विरोध की बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए - उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उप मुख्यमंत्री जगदीशदेवड़ा एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं सागर सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने भाजपा कार्यालय देवास में वीबी-जी रामजी योजना को लेकर पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है वीबी-जी रामजी जी योजना। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज दुनिया भारत की ओर देख रही हैं। वीबी-जी रामजी योजना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर गांवों को समृद्ध बनाएगी। इस योजना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है, जबकि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन काम मिलता था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कांग्रेस के शासनकाल में इस योजना में 35 हजार करोड़ मिलते थे, जिसे बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 74 हजार करोड़ किया और अब सुधारों के साथ लागू की जा रही इस योजना का बजट बढ़ाकर 95 हजार करोड़ कर दिया है। बजट में यह बढ़ोत्तरी कांग्रेस के शासनकाल के समय से लगभग तीन गुना अधिक है। प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को जमीन पर उतार रहे हैं। कृषि वर्ष 2026 में कृषि को उद्योग और रोजगार से जोड़कर सरकार किसानों की आय बढ़ाने का कार्य करेगी। कृषि वर्ष में वीबी-जी रामजी योजना से कृषि आधारित उद्योगों को नया विस्तार मिलेगा। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार 15 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाकर कृषि को रोजगार और उद्योग का सशक्त माध्यम बनाएगी। यह सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कांग्रेस को इस योजना का विरोध की बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा पार्टी के भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सागर सांसद ने कहा कि वीबी-जी रामजी अधिनियम से गांवों में अधोसंरचना का विकास होगा और विकास की नई क्रांति आएगी। वीबी-जी रामजी योजना में गरीबों, मजदूरों को अब 100 दिन के बजाय बजाय 125 दिन मजदूरी मिलेगी। कांग्रेस योजना को लेकर भ्रम फैलाकर ग्रामीणों को गुमराह कर रही है। इस योजना में पंचायतों को भी कार्य करने का अधिकार दिया गया है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को धरातल पर उतारने वाला राष्ट्रीय स्तर का मिशन है।

आजीविका का दायरा भी बढ़ाया गया है- जगदीश देवड़ा

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना को आवश्यकता के अनुरूप सुधार करके देश भर में लागू किया है। इस योजना को लेकर छह माह में राज्य सरकारों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी करनी है। अब मजदूरों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी निश्चित रूप से रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। कौशल और उद्यमिता के साथ इस योजना को जोड़कर रोजगार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सुधारों के साथ लागू की जा रही नई योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40 प्रतिशत की राशि वहन करेगी। कई मामलों में पहले केंद्र सरकार ही निर्णय लेता था, लेकिन अब राज्य सरकारें भी गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास को ध्यान में रखकर कार्यों को शामिल कर सकते हैं। नरेगा में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊजा, जैविक खाद इकाई, बाढ़ आश्रय स्थल, आपदा में क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार एवं रखरखाव जैसे कार्य शामिल नहीं थे। नई योजना में यह सभी कार्य शामिल किए गए हैं। जैविक खाद निर्माण इकाइयां, पशुपालन, मुर्गी-पालन शेड, मत्स्य पालन संबंधी निर्माण कार्यां, नर्सरी निर्माण, भवन-निर्माण सामग्री उत्पादन इकाई निर्माण का प्रावधान भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए किया गया है।

योजना में पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं- उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए होने वाले कार्यों की जियो-टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली तथा नियोजित सभी श्रमिकों को त्वरित एवं उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तथा बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता के लिए ग्राम-सभा द्वारा सोशल ऑडिट भी कराने का प्रावधान है। नई योजना में पंचायतीराज संस्थाओं जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा राज्य परिषद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। श्रीमिकों का पंजीकरण करने, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। भौगोलिक स्थिति, नगरीकरकण की दिशा में प्रगति जैसी बातों को योजना निर्माण के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। नई योजना से जनकल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं मजदूर, राज्य 60 दिन कर सकते हैं अधिसूचित- उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा पात्र मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, जबकि नई योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पुरानी योजना में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नई योजना में कृषि के व्यस्ततम समय जैसे बुवाई, कटाई के दौरान पर्याप्त कृषि श्रमिकों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है। नई योजना में राज्यों को 60 दिन अधिसूचित करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत फसलों की बुवाई, कटाई के समय को सम्मिलित कर खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस तरह 125 दिन के साथ मजदूरों को 60 दिन खेती किसानी में भी कार्य करने के लिए मिलेंगे। नई योजना में मजदूरी समय पर देने का प्रावधान किया गया है।

सेक्टर बैठक सह प्रशिक्षण आयोजित, प्रस्फुटन समितियों को दिया गया मार्गदर्शन

अकोदिया/ अमर सिंह मेवाडा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अकोदिया मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत ब्लॉक शाजापुर के सुन्दरसी सेक्टरङ्क5 में प्रस्फुटन समितियों की सेक्टर बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह बैठक नवांकुर संस्था आराधन जन कल्याण सामाजिक समिति द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सेक्टर की पाँच प्रस्फुटन समितियों–सुंदरसी, सेमली, कालीसिंध, उमरोद देवास एवं देवला बिहार–के कुल 35 सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता श्री तेज सिंह जी राठौड़, श्री देवीसिंह जी छावड़ी (सरपंच), सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य श्री राजेंद्र जी राठौड़, श्री बलरामसिंह जी डोडिया , परामर्शदाता श्री बहादुर जी सोलंकी एवं नवांकुर संस्था के अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात नवांकुर संस्था द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। एवं सभी प्रशिक्षणार्थियों को फाइल फोल्डर पेन डायरी व समितियों के कार्ययोजना की प्रति भी दी गई।

उद्बोधन में नवांकुर संस्था के अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जी ने सेक्टर में किए जा रहे कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। सरपंच श्री देवी सिंह जी ने ग्राम स्तर पर समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।

सामाजिक कार्यकर्ता श्री तेज सिंह जी ने उपस्थित सदस्यों से ग्राम विकास के लिए आगे बढ़कर कार्य करने का आह्वान किया। सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य श्री राजेंद्र जी राठौड़ ने पौधारोपण के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। परामर्शदाता श्री बहादुर जी सोलंकी ने समिति सदस्यों को ग्राम में नए कार्य प्रारंभ करने हेतु छात्रों से संपर्क कर उन्हें जन अभियान परिषद से जोड़ने की जानकारी दी।

ब्लॉक समन्वयक श्री बसंत रावत ने प्रस्फुटन समितियों को ग्राम में बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया, आगामी कार्ययोजना, दस्तावेजीकरण, दीवार लेखन एवं समिति में पारदर्शिता बनाए रखने संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

जिला समन्वयक श्री विष्णु प्रसाद नागर जी ने ग्राम में ग्राम उत्सव आयोजित करने, ग्राम की प्रतिभाओं को सम्मानित करने तथा बुजुर्गों के साथ बैठकर ग्राम का इतिहास संकलित करने एवं नवाचार करने पर जोर दिया।

बैठक में डॉ. राजेंद्रसिंह जी डोडिया, हुकुम जी कुशवाह, विक्रमसिंह जी, सीमा जी जैसवाल, अरुण जी बैरागी, अंगूरीवाला जी जायसवाल, लता बाघेला, सुधा बैरागी, अजय जी परमार, चंदन जी, सुगन जी कुम्भकार, लक्ष्मीनारायण जी, शिवराज सिंह जी, शक्तिसिंह जी रूपपुरा, सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री बलरामसिंह जी डोडिया ने किया एवं आभार प्रदर्शन ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सुंदरगढ़ के अध्यक्ष श्री राजेंद्रसिंह जी राठौड़ द्वारा किया गया।

पूर्व सांसद छतरसिंह दरबार के जन्मदिन पर आत्मीय स्वागत

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पूर्व सांसद छतरसिंह दरबार के जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पूर्व एलडीबी अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि महेंद्रसिंह शक्तावत के नेतृत्व में स्थानीय प्रतिनिधि मंडल ग्राम लुन्हैरा (मनावर) पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद का पुष्पहारों से आत्मीय स्वागत कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर महेंद्रसिंह शक्तावत ने कहा कि छतरसिंह दरबार तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र को निरंतर विकास की सौगातें मिली हैं। वर्ष 2019 से 2021 तक कोरोना महामारी के कारण दो वर्षों तक किसी भी सांसद को सांसद निधि की राशि प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसके बावजूद पूर्व सांसद ने जनसंपर्क और मार्गदर्शन के माध्यम से क्षेत्रवासियों से संवाद बनाए रखा। इसके बाद शेष तीन वर्षों में जब सांसद निधि उपलब्ध हुई, तो बदनावर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यों हेतु राशि स्वीकृत कराई गई। सड़क, भवन, सामुदायिक सुविधाओं सहित अनेक विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र को मिली, जिससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि छतरसिंह दरबार के पूर्व के दो कार्यकालों में भी बदनावर विधानसभा सहित आसपास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य कराए गए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संपर्क मार्गों के क्षेत्र में किए गए कार्य आज भी उनकी विकासशील सोच और जनप्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पूर्व सांसद के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की तथा उनके योगदान को स्मरण करते हुए आभार व्यक्त किया।

ग्वालियर जिला प्रशासन की मानवीय पहल कलेक्ट्रेट में प्रारंभ हुआ विश्राम कक्ष सह मातृ शिशु देखभाल केन्द्र

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में बच्चों और माताओं की सुविधा के लिए विश्राम कक्ष सह मातृङ्कशिशु देखभाल केंद्र का निर्माण कराया गया है। यह केंद्र विशेष रूप से उन माताओं और छोटे बच्चों के लिए स्थापित किया गया है, जो विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए कलेक्ट्रेट आते हैं और अपने कार्य के लिये कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप संवेदनशील प्रशासन की दिशा में ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने यह पहल की है। गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ इस केन्द्र का शुभारंभ किया । इस मौके पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्य करने वाली महिला अधिकारियों के साथ-साथ कलेक्ट्रेट में अपने कार्य से आई महिलायें और बच्चे भी शामिल हुए। शुभारंभ के अवसर पर ही बच्चों ने कक्ष में स्थापित किए गए खिलौनों का भी आनंद लिया।

इस नवाचार के अंतर्गत माताओं को अपने शिशुओं के पोषण, देखभाल एवं पालन के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। केंद्र में माताओं के बैठने एवं विश्राम की व्यवस्था के साथ-साथ बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान, स्वच्छता, पीने का पानी एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं। ऐसे में माताओं को शिशु को स्तनपान कराने, उसकी देखभाल करने या कुछ समय विश्राम करने में कठिनाई होती थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह शासन विश्राम कक्ष एवं मातृङ्कशिशु केंद्र विकसित किया गया है।

ग्वालियर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने बढ़ेगी खेल सुविधाएं

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्वालियर से राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकें इसके लिए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खेल की सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने गत रात्रि एकलव्य खेल परिसर स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स का अवलोकन करते हुए दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय मौजूद थे। अवलोकन में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्देश दिए कि ग्वालियर में बेहतर खिलाड़ी तैयार हो सकें इसके लिए जिन सुविधाओं की अवश्यकता हो उनके प्रस्ताव बनाकर तैयार करें। इन प्रस्ताव को केंद्र एवं प्रदेश सरकार को भेजा जाएंगा ताकि वहां से खेल को प्रोत्साहित करने वाले योजनाओं से ग्वालियर में बेहतर संसाधन तैयार किए जा सकें।

शहर में खेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं खिलाडियों को बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नगर निगम द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्ध खेल सुविधाओं, मैदानों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं तथा आवश्यक सुधार कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए ठोस और व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के युवाओं और उभरते खिलाडियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो उन्हें आधुनिक एवं समुचित खेल संसाधन उपलब्ध कराने की।

खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के सतत प्रयास से मिली सौगात

प्रतिदिन चलने वाली गोवा एक्सप्रेस ट्रेन का बुरहानपुर में मिला स्टॉपेज क्षेत्रवासी ने कहा धन्यवाद सांसद जी

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के प्रयास से बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन चलने वाली गोवा एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की सौगात मिल गई है। उनके कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर 15 वी ट्रेन के ठहराव की स्वीकृति मिली है। इस सौगात के लिए सांसद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार माना है।

सांसद ने अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया अपने नाम - डीआरयूसीसी सदस्य पंकज नाटानी ने बताया कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटील सतत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, चेयरमैन रेलवे बोर्ड सहित अधिकारियों से संपर्क व पत्राचार करते हुए संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर,नेपानगर और खंडवा में रेलवे को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा के राजनीतिक इतिहास में वे ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जिन्होंने अब तक 15 ट्रेनों का स्टॉपेज दिलाकर अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है।

सांसद के प्रयास से बुरहानपुर स्टेशन पर इन ट्रेनों के मिले स्टॉपेज।

लोकमान्य तिलक बनारस एक्सप्रेस, अहमदाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस, जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस, अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस, जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस, पूणे जबलपुर एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस अब जल्द जारी होगा शेड्यूल प्रतिदिन गोवा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12779/12780 के स्टॉपेज से बुरहानपुर से अप में सातारा,पुणा, गोवा जाने तथा डाउन में भोपाल, ह निजामुद्दीन जाने में यात्रियों को सुविधा होंगी। ट्रेन के स्टॉपेज की मंजूरी मिल गई है जल्द ही इसकी तारीख और समय का शेड्यूल भी जारी हो जायेगा। इस ट्रेन के ठहराव को लेकर लगातार मांग उठ रही थी।

राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ

देश में पहली बार आधुनिक तकनीक से 4K वॉटर प्रोजेक्शन से होगा ऐतिहासिक इवेंट

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरुवार को बड़े तालाब स्थित वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी पहुँचकर खेलो एमपी यूथ गेम्स की लॉन्चिंग तैयारियों का निरीक्षण किया। मंत्री श्री सारंग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक खेल प्रेमियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा सुरक्षा, तकनीकी एवं व्यवस्थागत सभी इंतजाम पूर्णतः पुख्ता हों।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती 'राष्ट्रीय युवा दिवस' 12 जनवरी को खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। यह शुभारंभ कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में शाम 6 बजे बड़े तालाब से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार लॉन्चिंग इवेंट के दौरान दर्शकों को 4य वॉटर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। यह वॉटर प्रोजेक्शन दर्शकों को एक इमर्सिव और सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगा, जो अब तक राज्य स्तर के किसी भी खेल आयोजन में देखने को नहीं मिला है।

देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर ऐतिहासिक लॉन्चिंग- देश में पहली बार किसी राज्य स्तरीय यूथ स्पोर्ट्स इवेंट की लॉन्चिंग फ्लोटिंग स्टेज पर की जाएगी, जहाँ 4य वॉटर प्रोजेक्शन इस ऐतिहासिक समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। भोपाल के बड़े तालाब की प्राकृतिक भव्यता के बीच जल-परदे पर अत्याधुनिक 4य तकनीक के माध्यम से खेलो एमपी यूथ गेम्स की थीम, लोगो, विजुअल स्टोरी और खेल भावना को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक प्रस्तुति के साथ हाई-क्वालिटी विजुअल डिस्प्ले, टॉर्च लाइटिंग के माध्यम से आकर्षक फायर वर्क तथा 20 फीट ऊँची 'लार्जर दैन लाइफ' जर्सी जैसे विशेष आकर्षण समारोह की भव्यता को बढ़ायेंगे। आधुनिक तकनीक और खेल संस्कृति के इस अद्वितीय संगम के माध्यम से यह शुभारंभ समारोह मध्यप्रदेश की नवाचार क्षमता, खेल प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगा।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि शुभारंभ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम्स के लोगो, मैस्कॉट, एंथम एवं आधिकारिक जर्सी का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। यह क्षण खेलो एमपी यूथ गेम्स की पहचान और भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करेगा। इस अवसर पर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ खेल प्रशासक भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ समारोह विशेष रूप से आकर्षक एवं यादगार बनाया गया है। इस अवसर पर ताल-तलैयों की नगरी भोपाल के ऐतिहासिक तालाबों की भव्यता दिखेगी। शुभारंभ समारोह के माध्यम से एमपी की पहचान केवल खेलों के राज्य के रूप में ही नहीं, बल्कि संस्कृति, सौंदर्य और युवाशक्ति के केंद्र के रूप में भी देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। यह आयोजन खिलाड़ियों, दर्शकों और आमजन के लिए प्रेरणादायी एवं उत्साहवर्धक अनुभव सिद्ध होगा।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यह देश में पहली बार हो रहा है, जब खेल विभाग के साथ सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर समन्वित रूप से यूथ गेम्स का आयोजन एवं संचालन कर रहे हैं। यह पहल खेल विभाग का एक ऐतिहासिक और नवाचारी कदम है। खेलो एमपी यूथ गेम्स केवल एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भविष्य की राज्य टीम चयन प्रक्रिया का सशक्त, व्यवस्थित और पारदर्शी मंच बनेगा। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान प्रारंभिक स्तर पर ही हो सकेगी, जिससे उन्हें आगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने का सशक्त अवसर प्राप्त होगा।

खेलो एमपी यूथ गेम्स की चयन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएँ 12 से 16 जनवरी 2026, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ 16 से 20 जनवरी 2026, संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएँ 21 से 25 जनवरी 2026 तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएँगी। यूथ गेम्स के अंतर्गत कुल 28 खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। खेल संघों के साथ बेहतर एवं प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा समन्वय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रतियोगिताओं का आयोजन इस सिद्धांत पर किया जाएगा कि जिन खेलों की परंपरा एवं लोकप्रियता जिस क्षेत्र में है, वहीं संबंधित खेलों का आयोजन किया जाए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर एवं नर्मदापुरम में प्रस्तावित हैं। ब्लॉक स्तर से प्रारंभ होने वाली इस चयन प्रक्रिया में जिला स्तर पर प्रदेश के 313 विकासखंडों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। राज्य स्तर पर प्रदेश के 10 संभागों की टीमें प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने किया खादी एक्सपो का शुभारंभ

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्वालियर व्यापार मेला के समीप स्थित दस्तकारी हाट में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ÷खादी एक्सपो÷ का शुभारंभ किया। इस दस्तकारी हाट में देश के विभिन्न राज्यों के कला-शिल्पी एवं बुनकर एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प उत्पाद लेकर आए हैं। खादी एक्सपो के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि ऐसे मेलों के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र, स्व-सहायता समूह एवं व्यक्तिगत रूप से हस्तशिल्प उत्पाद से जुड़े छोटे-छोटे व्यवसाइयों के उत्पादों को बिक्री के लिये अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। साथ ही शिल्पकला प्रेमियों को उचित दाम पर अच्छे उत्पाद मिल जाते हैं। इससे लोकल फॉर वोकल अवधारणा को भी बल मिलता है। मध्यभारत खादी संघ जीवाजीगंज द्वारा आयोजित किए गए इस खादी एक्सपो में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, बिहार व कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्पी अपने-अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध उत्पादों को बिक्री के लिये लेकर आए हैं।

खासतौर पर कश्मीरी पसमीना की शॉलें व अन्य गर्म कपड़े, लखनवी चिकन, भागलपुरी सिल्क साड़ियां, गुजराती कढ़ाईदार वस्त्र, मधुवनी व नालंदा कसीदाकारीयुक्त विशेष वस्त्र, जयपुरी रजाईयां व ज्वैलरी सहित अन्य राज्यों के एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प उतपाद खादी एक्सपो के विशेष आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं।

इसके अलावा जीआई टैग युक्त पेपरमेशी कला आर्ट, कोल्हूघानी से निर्मित सरसों, मूंगफली व तिल तेल, अगरबत्ती, मसाले, शहद व गाय का शुद्ध घी खादी एक्सपो में उपलब्ध है। आरंभ में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को खादी की माला पहनाकर, दीप प्रज्ज्वलन व फीता काटकर खादी एक्सपो का उदघाटन किया। उन्होंने खादी एक्सपो लगाने के लिये मध्यभारत खादी संघ की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने एक्सपो में लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया।

राजू आदिवासी को मिली झोपडी से मुक्ति, अब रहते हैं पक्के मकान में

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनपद पंचायत भितरवार से लगभग 12 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव मागरपुर के आदिवासी दफाई में रहने वाले राजू ने कभी सोचा नहीं था कि अपनी छोटी सी आय से कभी अपना स्वयं का पक्का मकान बना पाएगा। वह जितना कमाता था उससे उनके परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजर-बसर हो पाता था। वह आदिवासी दफाई में अपनी कच्ची झोपड़ी में चार बेटियों के साथ रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का सहारा मिलने से राजू की जिंदगी बदल गई। आज राजू अपनी चार लाडलियों के साथ खुद के पक्के मकान में रहता है और आय बढ़ाने के लिए मनरेगा से उसे 95 दिन का रोजगार भी मिला है। इसके साथ ही जीवन में अमूलचूल बदलाव लाने के लिए शासन ने राजू के सामने योजनाओं की झड़ी लगा दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राजू को पक्का और सुरक्षित घर मिला। इस योजना से उसके परिवार को स्थायित्व, सुरक्षा और आत्मसम्मान का भाव भी प्रदान किया है। घर मिलने और मनरेगा से रोजगार मिलने से उसके बच्चों की पढ़ाई नियमित हुई और परिवार का जीवन अनुशासित व सुखद हो गया। इसके साथ ही राजू को उज्ज्वला योजना से गैस सिलेण्डर मिला जिससे परिवार को चूल्हें के धुएं से मुक्ति मिली। इसी प्रकार विद्युत विभाग ने उसे बिजली का कनेक्शन दिया जिससे अब उसकी बेटियां रात में भी पढ़ाई कर पा रही है। साथ ही पीने के लिए घर तक पानी की लाइन, शौचालय मिला जिससे गंदगी से छुटकारा मिला है। इसके साथ ही परिवार की सीमित आय होने के चलते शासन की ओर से राशन मिल रहा है। जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग से सहरिया पोषण आहार दिया जा रहा है।

कलेक्टर, एसपी ने कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर कथा की तैयारियों का किया निरीक्षण

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कुबेरेश्वर धाम में आगामी फरवरी माह में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा के दृष्टिगत कलेक्टर श्री बालागुरू के., पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कथा स्थल की सभी व्यवस्थाओं को देखा और संबंधित विभागीय अधिकारियों, आयोजन समिति के सदस्यों, अधिकृत एजेंसियों एवं ठेकेदारों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि कथा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजन से पूर्व सभी व्यवस्थाएं समयसीमा में पूर्ण की जाएं, ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असुविधा अथवा सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलग-अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे अपने दायित्वों को पूरी गंभीरता के साथ समझें और मौके पर उपस्थित रहकर कार्य करें।

कलेक्टर ने आयोजन समिति के सदस्यों से भी चर्चा करते हुए कहा कि समिति के सभी सदस्य अपने-अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों को भली-भांति समझें तथा प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में देरी या लापरवाही सीधे तौर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि कथा के दौरान किसी भी स्थिति में जाम की समस्या उत्पन्न न हो। इसके लिए पार्किंग स्थलों का स्पष्ट चिन्हांकन किया जाए तथा श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग जोन निर्धारित किए जाएं। ऑटो स्टैंड की समुचित व्यवस्था, स्टैंड तक पहुंचने के लिए उचित ढलान (स्लोप) निर्माण तथा वाहनों की आवाजाही के लिए सुव्यवस्थित मार्ग बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि हाईवे एवं मुख्य मार्गों पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

कलेक्टर ने सड़क मार्गों पर पर्याप्त संख्या में संकेतक, फ्लेक्स एवं सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मार्ग संबंधी किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट सिस्टम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए, जिससे यातायात एवं आवश्यक सूचनाएं समय-समय पर श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा सकें।

भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर ने कथा स्थल को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में जिम्मेदार अधिकारी एवं वालंटियर तैनात किए जाएं, ताकि भीड़ का नियंत्रण प्रभावी रूप से किया जा सके। फायर सेफ्टी को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि फायर ब्रिगेड, अग्निशमन उपकरण एवं आपातकालीन व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध रहें।

पेयजल, स्वच्छता एवं बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि आयोजन स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। प्याऊ, टोंटीयुक्त नल कनेक्शन एवं जल टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ-सफाई के लिए अस्थाई एवं चलित शौचालयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्तिच करने तथा नियमित सफाई के लिए सफाई कर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। विद्युत व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सभी बिजली कनेक्शन सुरक्षित हों, नो-मेन जोन का पालन किया जाए तथा विद्युत विभाग की टीम 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नेटवर्क व्यवस्था एवं एलईडी स्क्रीन व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कथा के दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को कार्यक्रम का स्पष्ट प्रसारण और सूचनाएं मिले तथा संचार व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन के दौरान रुद्राक्ष वितरण पूरी तरह से बंद रहेगा और इस संबंध में स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए जाएं, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तृत बैठक आयोजित की

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समारोह को गरिमामय, सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराना हैं। बैठक में समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को विभागवार दायित्व सौंपते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पीएम श्री शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ग्राउंड पर प्रातः 9:00 बजे किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है, अतः आयोजन में गरिमा, अनुशासन एवं समयपालन का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए मैदान की समुचित साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, बांस-बल्ली एवं मंच की आकर्षक सज्जा, प्रवेश द्वार की साज-सज्जा, पार्किंग व्यवस्था, परेड ग्राउंड के ट्रैक की तैयारी तथा दर्शक दीर्घा की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था पूर्णतः झण्डा संहिता के अनुरूप की जाए। राष्ट्रीय गान पुलिस बैंड द्वारा बजाया जाएगा तथा राष्ट्रपति जी की जय का उद्घोष विधिवत रूप से किया जाएगा।

समारोह के दौरान विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित बैठक व्यवस्था, परेड निरीक्षण हेतु वाहन, सुदृढ़ साउंड सिस्टम, टेंट एवं कुर्सियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की समुचित व्यवस्था रखने पर विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर ने अतिथियों के स्वागत एवं सत्कार, निमंत्रण पत्रों के समय पर वितरण, मीडिया समन्वय, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण की पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त झांकियों के चयन, उनकी विषयवस्तु एवं प्रस्तुति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के समस्त शासकीय भवनों को आकर्षक रोशनी से जगमग किया जाए। साथ ही 26 जनवरी की संध्या को आयोजित होने वाले भारत पर्व कार्यक्रम को भी गरिमामय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बनाने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के तहत जिले में 12 से 31 जनवरी तक होगा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार '' खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 '' का आयोजन जूनियर आयु वर्ग में खेलों की लोकप्रियता व सम्बंधित खेल में प्रतिवर्ष होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है।

इसका आयोजन विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर 12 से 31 जनवरी 2026 के मध्य किया जाना है, जिसमें विकासखंड स्तरीय चयन ट्रायल 16 जनवरी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता 19 जनवरी को आयोजित होगी। खेलों एमपीयूथ गेम्स में कुल 28 खेलों को शामिल किया गया है, जिन्हें तीन अलग-अलग श्रेणियों (3-चरण, 4-चरण और सीधे राज्य स्तर) में बांटा गया है।

तीन चरण (ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर) में 11 खेलो हॉकी बॉक्सिंग एथलेटिक्स खो - खो, तैराकी, टेबल - टेनिस, मलखम, कुश्ती, जूडो, शतरंज, वेटलिफ्टिंग को शामिल किया गया है।

वहीं चौथे चरण (ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर) में कुल 10 खेल वॉलीबॉल क्रिकेट बैडमिंटन पिट्ठू बास्केटबॉल टेनिस योगासन रस्साकस्सी और कबड्डी को शामिल किया गया है और सीधे राज्य स्तर पर कुल 7 खेलों आर्चरी, ताइक्वांडो, काइकिंग कैनोइंग, रोइंग, फेन्सिंग, शूटिंग एवं थ्रो बॉल को शामिल किया है।

इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की आयु 19 वर्ष से कम (जन्म 1 जनवरी 2007 या उसके बाद) होनी चाहिए और खिलाड़ी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी अथवा मध्यप्रदेश खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, सहभागिता कर सकता है।

सभी इच्छुक खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए विकासखंड स्तर पर पंजीयन अनिवार्य होगा। यह कार्य संबंधित ग्रामीण युवा समन्वयक द्वारा संचालनालय द्वारा पृथक से प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन लिंक पर किया जाएगा।

विकासखंड स्तर पर पंजीकृत खिलाड़ी जिला स्तर पर प्रतिभागिता करेंगे तथा जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी या दल को संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी संभाग/ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अग्रेषित करेंगे।

इसी प्रकार संभाग स्तर पर चयनित खिलाड़ी या दल को संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अग्रेषित करेंगे। खिलाड़ी को पोर्टल पर पंजीयन में यदि कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान संबंधित ग्रामीण युवा समन्वयक द्वारा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के सहयोग से किया जावेगा।

कलेक्टर ने की अनेक विभागों की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में नगरीय निकायों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, शहरी विकास अभिकरण, उद्योग विभाग, एनआरएलएम एवं रोजगारङ्कस्वरोजगार से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं अन्य गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक मे जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (वाटरशेड), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अन्य अभिसरण योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत समग्र आईडी सीडिंग रिपोर्ट समीक्षा के दौरान सीडिंग कार्य में तेजी लाने और शेष पात्र हितग्राहियों को शीघ्रता से योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (वाटरशेड) की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी लंबित स्वीकृतियों को शीघ्र पूर्ण कर कार्यों को गति दी जाए। इसके साथ ही ÷एक बगिया माँ के नाम÷ योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर उद्यानिकी पौधरोपण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वच्छता कार्यों की निरंतर निगरानी, ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा में योजना से जुड़ी एजेंसियों, रसोईया कम हेल्पर की स्थिति, माह नवंबर एवं दिसंबर 2025 के खाद्यान्न उठाव तथा जनवरीङ्कफरवरी 2026 के परिवहन एवं उठाव की प्रचलित कार्यवाही की जानकारी दी गई।

मंदिरों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का किया गया आह्वान

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दूसरे फेज में समाज के प्रभावशाली माध्यमों को जोड़ते हुए धार्मिक स्थलों पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही है। शासन निर्देशानुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारे के साथ-साथ विवाह से जुड़े सेवा प्रदाता जैसे वेडिंग हॉल, बैंडबाजा, कैटरिंग, टैंट हाउस, विवाह पत्रिका प्रिंटिंग को अभियान में शामिल किया गया है।

इसी तारतम्य में कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री आर एस बघेल के मार्गदर्शन में 08 जनवरी 2026 को वन स्टॉप सेंटर झाबुआ की टीम द्वारा गायत्री परिवार के सदस्य के सहयोग से शहर में स्थित गायत्री शक्तिपीठ मदिर में बाल विवाह के प्रति जागरूकता कार्यक्रम एवं बाल विवाह से संबंधित पोस्टर चस्पा किया गया।

कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की केसवर्कर श्रीमती सोनम बामनिया एवं परामर्शदाता सुश्री रानू राठौर द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका अथवा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में सहयोग करने या प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जुर्माने व करावास का प्रावधान है। गायत्री शक्तिपीठ की जिला समन्वयक श्रीमती नलिनी ने आम जन से अपील की यदि कही भी बाल विवाह की जानकारी या शंका हो तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाईन 1098, पुलिस 112 अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचित करें तथा झाबुआ जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने में सहयोग करे।

ग्राम छापरी में जल जागरूकता एवं जल परीक्षण प्रशिक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन में जिले में जल जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज 08 जनवरी 2026 को कार्यपालन यंत्री के मार्गदर्शन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग झाबुआ द्वारा विकासखंड रामा के ग्राम छापरी कालीदेवी की ग्राम पंचायत में जल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत नल-जल योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी भवन में उपस्थित बच्चों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों को दूषित पेयजल से होने वाली जनित बीमारियों की रोकथाम तथा शुद्ध पेयजल के महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर एफटीके किट के माध्यम से पेयजल स्रोतों का जल परीक्षण कर उसका व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे ग्रामीण स्वयं जल की गुणवत्ता की जांच कर सकें। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों को शुद्ध पेयजल के उपयोग हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला सलाहकार श्री धूलिया बामनिया एवं विकासखंड समन्वयक सुश्री अंकिता पाठक का विशेष योगदान रहा।

ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल व्यवस्था की होगी जाँच

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभागीय राज्यमंत्री राधा सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सम्पूर्ण प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता जाँच का अभियान चलायें। यह अभियान 15 फ़रवरी तक पूर्ण होना चाहिए। बैठक में मंत्री श्री पटेल ने स्पष्ट किया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से पहुँचे। योजनाओं का प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। समीक्षा बैठक में मंत्री श्री पटेल ने विकसित भारत- गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (जी राम जी) के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी प्रशासनिक, तकनीकी एवं कार्यात्मक तैयारियाँ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएँ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर सुदृढ़ हो सकें। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को प्रतिमाह अनिवार्य रूप से फील्ड विजिट कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिससे जिलों में किए जा रहे अच्छे नवाचारों को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सके। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री श्री पटेल ने जिलों के कार्य निष्पादन के आधार पर मासिक ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर ग्रेडिंग सूची जारी करने के निर्देश भी दिए, जिससे अधिकारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक जल स्रोतों की सैंपलिंग कर जांच कराई जाए तथा पुनः अप्रैल माह में अनिवार्य रूप से जल गुणवत्ता की समीक्षा की जाए।

बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं की रेमेडियल कक्षाओं का औचक निरीक्षण रेमेडियल कक्षाओं में लापरवाही पर सख्ती, प्राचार्य व शिक्षकों को नोटिस के निर्देश

बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार हेतु रेमेडियल कक्षाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में सुधार तथा उनकी प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जिले के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों हेतु रेमेडियल कक्षाओं के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। इन कक्षाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) एवं तहसीलदारों को आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि जिले की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में रेमेडियल कक्षाओं का संचालन तो किया जा रहा है, किंतु कई विद्यालयों में इन कक्षाओं का संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद सुश्री तनुश्री मीणा ने शासकीय उमावि करडावद में निरीक्षण किया गया। जिसमें ज्ञात हुआ कि रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जा रही थीं, परंतु उनकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। चिन्हित विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम रही तथा उन्हें विद्यालय लाने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। कक्षा 12वीं में अंग्रेजी विषय के लिए पंजीकृत 73 में से केवल 33 तथा कक्षा 10वीं में 49 में से 34 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला श्री महेश मंडलोई द्वारा सांदीपनि शासकीय विद्यालय, थांदला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्षा 10वीं एवं 12वीं की रेमेडियल कक्षाएं अंग्रेजी विषय की संचालित पाई गईं। कक्षा 10वीं में कुल 110 में से 86 विद्यार्थी तथा कक्षा 12वीं में 91 में से 52 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए।

इसी प्रकार, एसडीएम मेघनगर श्रीमती रीतिका पाटीदार द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रंभापुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित विशेष कोचिंग (रेमेडियल) कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही विद्यालय में कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति पंजी के अवलोकन में यह भी सामने आया कि प्राचार्य सहित पदस्थ शिक्षकों के हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं थे तथा किसी भी प्रकार के अवकाश आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तहसीलदार थांदला श्री सुकदेव डावर द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परवलिया (तहसील थांदला) का औचक निरीक्षण किया गया। यहां कक्षा 10वीं एवं 12वीं की रेमेडियल कक्षाएं अंग्रेजी विषय की संचालित पाई गईं। कक्षा 10वीं में कुल 160 में से 105 विद्यार्थी तथा कक्षा 12वीं में 156 में से 45 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए।

रेमेडियल कक्षाओं के समुचित संचालन में पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नेहा मीना ने सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित किया है कि जिले में बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार हेतु विभागीय निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रेमेडियल कक्षाओं का संचालन व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से किया जाए तथा सहायक आयुक्त एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (ब्लॉक) रोस्टर के अनुरूप नियमित निरीक्षण कराए। जहां रेमेडियल कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है, वहां संबंधित प्राचार्य एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शासकीय बाल विनय मंदिर में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ

बड़वानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर के शासकीय बाल विनय मंदिर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस विद्यालय में कक्षा 9वीं में 280 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इच्छुक विद्यार्थी 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 8 फरवरी है। विद्यार्थी अपना आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लिंक पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है। आवेदन शुल्क 200 रुपये है। प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त होंगे। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इंदौर के बाहर से आने वाले 100 बालक एवं 100 बालिकाओं के लिए हॉस्टल की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन की सुविधा, विभिन्न विषयों के लिए पृथक-पृथक प्रयोगशालाएं, आईटी लैब, आईसीटी लैब, खगोलीय लैब एवं रोबोटिक्स लैब, कंप्यूटर शिक्षण की सुविधा, व्यवसायिक शिक्षा का अध्यापन, एनसीआरटी पैटर्न पर गुणवत्ता युक्त शिक्षण, खेल, एनसीसी, स्काउट/गाइड एवं संगीत की पाठ्येत्तर सुविधा, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु काउंसलिंग / कोचिंग, निःशुल्क बालक एवं बालिका छात्रावास की सुविधा, न्यूनतम शुल्क पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा विशेष सुविधा है। विद्यालय के विद्यार्थियों का नीट एवं जेईई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में चयनित होकर भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, शत - प्रतिशत परीक्षा परिणाम, राष्ट्रीय स्तर पर खेल, साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय बाल विनय मंदिर, नेहरू पार्क रोड इंदौर में संपर्क किया जा सकता है। मोबाईल नम्बर 9826563670, 9826593430 तथा 9340155283 पर भी संपर्क करने की सुविधा है।

महिला सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा : मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि शिक्षा, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से न केवल समाज को नई दिशा मिलती है, बल्कि प्रदेश और देश के विकास में भी ठोस योगदान मिलता है।

मंत्री सुश्री भूरिया आईएचएम भोपाल में ऊर्जस्विता - 2026 को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सम्मानित होने वाली विभूतियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि बाल संरक्षण एवं बाल देखरेख से जुड़े बच्चों के लिए विभाग पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर तथा बाल कोविड योजना के माध्यम से निरंतर लाभ पहुँचा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति- 2020 को लागू कर बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनकी देखरेख को सुनिश्चित किया है।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत-2047 के विजन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। Women Led Development की अवधारणा को अपनाकर भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से समाज सशक्त होता है और देश आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनता है। इसी दिशा में महिलाओं के सशक्तिकरण, अनुसंधान और उद्यमिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि वह जहाँ भी कार्यरत है, अपने दायित्वों का निर्वहन इस प्रकार करे कि समाज, प्रदेश और देश का विकास सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम में पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश शासन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके कौशल विकास और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम के अंत में मंत्री सुश्री भूरिया ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान और अनुभव से आमजन को भी जोड़ें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

गेंहू में अच्छे उत्पादन हेतु क्रांतिक अवस्थाएं महत्वपूर्ण- डॉ.बड़ोदिया

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ एस. के. बड़ोदिया द्वारा बड़वानी, पाटी एवं निवॉली विकासखण्ड में गेंहू फसल लेने वाले कुछ कृषकों के प्रक्षेत्रों का भ्रमण किया । जहॉ कहीं-कही. पर गेंहू फसल में सिंचाई एवं पोषण तत्वों के प्रबंधन की आवष्यकता देखी गयी । गेंहू फसल में पोषक तत्व प्रबंधन हेतु नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाष 120:60:40 किग्रा. अनुषंसित है, जिसमें एक तिहाई नत्रजन एवं पुरी मात्रा में फास्फोरस व पोटाष बुवाई के समय देना चाहिये । डॉ. बड़ोदिया ने बताया कि गेंहू फसल की 5-6 प्रमुख क्रान्तिक अवस्थाएं होती है ।

जड़ प्रर्वतन अवस्था (क्राउन रूट इनिषिएषन) यह अवस्था 20-25 दिन बाद होती हैयह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है इस समय मुख्य जड़े विकसित होती है ऐसे समय पानी की कमी से जड़ों का विकास रूक जाता है जिससे गेंहू की पैदावार प्रभावित होती है। साथ ही इस अवस्था में प्रथम सिंचाई के पहले या बाद में मिट्टी के अनुसार एक तिहाई (40 किग्रा.) नत्रजन देना चाहिए, जिससे पौधों का अच्छा विकास हेाता है।

कल्ले निकलने की अवस्था -यह अवस्था 40-45 दिन बाद होती है इस दौरान पौधों से कल्ले निकलते है पर्याप्त नमी से कल्ले स्वस्थ बनते है। इसके बाद शेष बची हुई एक तिहाई (40 किग्रा.) नत्रजन सिंचाई के बाद खेत में नमी होने की स्थिति में देना चाहिए । 3. गांठ बनने की अवस्था - यह अवस्था 60-65 दिन बाद होती है जिसमे इस समय तनों में गांठे बनती है पौधा लम्बा होने लगता है । पानी की कमी से पौधा कमजोर होने लगता है। इस दौरान 00:52:34 01 कि.ग्रा./ एकड़ 200 ली. पानी में घोलकर स्प्रे करें ।

फुल आने से पहले की अवस्था - यह अवस्था 80-85 दिन बाद होती है, फुल आने से पहले सिंचाई से फुल अच्छी तरह आते है, दांनो का भराव भी अच्छा होता है। 5. दुध बनने और दाना भरने की अवस्था- यह अवस्था 100-105 दिन बाद की होती है। इस अवस्था में दानों में दुध आता है एवं दाना भरता है। पानी की कमी से दाना सिकुड़ जाता है। इसलिए सिंचाई जरूरी है। बलियां बनते समय 0:0:50 1. कि.ग्रा./एकड़ की दर से 200 ली. पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिये । कोहरे के मौसम के खेतों में हल्की सिंचाई करे नमी से मिट्टी का तापमान कम नहीं होता और पौधों फसलों को गर्मी मिलती है । रात के समय खेत के चारों ओर मेंड़ो पर सूखी घास/पराली/कचरा जलाकर धुआं करे जिससे वातावरण में गर्मी बढ़ेगी और पाला नहीं जमेगा। साथ ही गन्धक 0.1 प्रतिषत घोल का छिड़काव करे यह पाले से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही कीटनाषकों एवं फंफुदनाषकों का प्रयोग मौसम साफ होने पर ही करना चाहिए ।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

शिवांगी परिसर मामला, हाईकोर्ट के फैसले को हाउसिंग बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती

इंदौर रोड स्थित गोयलाखुर्द की 3.093 हेक्टेयर भूमि से जुड़े विवाद की 23 जनवरी को सुनवाई - हाईकोर्ट ने अधिग्रहण निरस्त कर कब्जा लौटाने के दिए थे आदेश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शिवांगी परिसर आवासीय योजना से जुड़े बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कानूनी लड़ाई शुरू होने जा रही है। हाउसिंग बोर्ड ने इंदौर हाईकोर्ट के 3 जून 2024 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई आगामी 23 जनवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि यह मामला इंदौर रोड स्थित गोयलाखुर्द क्षेत्र की कुल 3.093 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है, जहां हाउसिंग बोर्ड द्वारा शिवांगी परिसर आवासीय योजना विकसित की जा रही थी। योजना के अंतर्गत 2.888 हेक्टेयर भूमि पर करीब 47 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत से 69 एमआईजी, 7 एलआईजी और 22 ईडब्ल्यूएस आवास प्रस्तावित थे। इसके अतिरिक्त 5445 वर्गमीटर क्षेत्र में 62 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से बहुमंजिला भवन निर्माण का भी भूमि पूजन किया जा चुका था।

किसानों की याचिका से पलटा मामला- निर्माण कार्य प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही 22 किसानों ने भूमि अधिग्रहण की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। किसानों का तर्क था कि जिस उद्देश्य से भूमि अधिग्रहित की गई थी, उसका उपयोग बदल दिया गया। सुनवाई के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और किसानों को दो सप्ताह के भीतर जमीन का कब्जा लौटाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट टिप्पणी की थी कि जिस भूमि का अधिग्रहण वृद्धाश्रम के उद्देश्य से किया गया था, उस पर आवासीय कॉलोनी विकसित करना उद्देश्य परिवर्तन की श्रेणी में आता है, जो विधिसंगत नहीं है।

निवेशकों और परियोजना को लगा झटका- हाईकोर्ट के फैसले से न केवल हाउसिंग बोर्ड को बड़ा झटका लगा, बल्कि शिवांगी परिसर में आवास पाने के लिए राशि जमा कर चुके 29 निवेशकों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। निर्माण कार्य कर रही भोपाल की संजना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम बंद कर साइट छोड़ दी थी। बाद में बोर्ड ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की, जिस पर 24 जून 2024 को यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश मिला।

अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद- हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री एनके गुप्ता के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। जिस पर आगामी 23 जनवरी को सुनवाई होना है। इधर जानकारों का कहना है कि यदि शीर्ष अदालत से बोर्ड के पक्ष में फैसला आता है तो परियोजना को दोबारा गति मिल सकती है और निवेशकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के चलते परियोजना की समय-सीमा और लागत दोनों के बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

ये है प्रकरण की पूरी पृष्ठभूमि

- 22 किसानों ने भूमि अधिग्रहण को हाईकोर्ट में दी चुनौती
- इंदौर हाईकोर्ट ने अधिग्रहण को बताया अवैध
- उद्देश्य परिवर्तन को माना कानून के खिलाफ
- किसानों को जमीन का कब्जा लौटाने के दिए थे आदेश
- 24 जून 2024 को रिव्यू पिटीशन पर यथास्थिति का आदेश

अवैध शराब के साथ पकड़ा बदमाश निकला वाहन चोर

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। बदनावर की ओर से बड़नगर की ओर अवैध शराब लेकर आ रहे बदमाश की खबर मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। उसके पास से जहरीली शराब से भरी केन बरामद की गई। पूछताछ में उसने बाइक चोरी करना भी कबूल कर लिया।

बड़नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार ने बताया कि कस्बा भ्रमण के दौरान खबर मिली थी कि भेरू मंदिर के पास बदनावर रोड से एक व्यक्ति थैली में कच्ची हाथ भट्टी से बनी शराब की केन छुपाकर बड़नगर की ओर आ रहा है। तत्काल एसआई हेमंत कटारे, एएसआई गोवर्धनदास बैरागी, प्रधान आरक्षक हेमराज खरे, नारायण सरा, राकेश रायकवार की टीम को घेराबंदी के लिये रवाना किया गया। टीम ने बदनावर मार्ग पर घेराबंदी कर थैली में प्लास्टिक की केन छुपाकर ला रहे व्यक्ति का पकड़ा और तलाशी ली। उसके पास से केन में भरी 10 लीटर जहरीली शराब बरामद हो गई। थाने लाकर पूछताछ करने पर आरोपी का नाम सुभाष पिता सिमुन राणा निवासी बड़ी धामनी थाना थांदला जिला झाबुआ होना सामने आया। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34, 49-ए का प्रकरण दर्ज किया गया। अन्य मामलों में पूछताछ करने पर उसने बाइक चोरी की वारदात भी कबूल कर ली। वाहन चोरी का खुलासा होने पर चोरी की बाइक बरामद करने का प्रयास किया गया। जो उसने बदनावर मार्ग पर झाड़ियों में छुपाकर रखना कबूल किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर बाइक बरामद की। जो एक दिन पहले ही सजन पार्क बड़नगर से चोरी की गई थी। थाना प्रभारी के अनुसार बाइक चोरी की शिकायत सुनील पिता मांगीलाल चंदेल ने दर्ज कराते हुए बताया था कि बाइक क्रमांक एमपी 13 ईएस 1746 उसके घर के समाने से चोरी हुई है। जिसे अवैध शराब के साथ हिरासत में आये बदमाश से बरामद कर लिया गया है। आरोपी बदमाश के खिलाफ चोरी की धारा का इजाफा कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से जेल भेजा गया है।

सांदीपनि चौराहा से उदयन मार्ग चौड़ीकरण का विरोध

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सांदीपनि चौराहा से उदयन मार्ग (विक्रम मार्ग) तक स्वीकृत 24 मीटर (लगभग 80 फीट) चौड़ी सड़क परियोजना पर क्षेत्रीय व्यापारियों और नागरिकों ने आपत्ति लेते हुए पुरजोर विरोध किया है। रहवासियों, व्यापारियों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपकर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस चौड़ीकरण को रोका नहीं गया तो दुकानदार और रहवासी मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे।

दरअसल कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से मार्ग चौड़ा करने के लिए भूमिपूजन किया था। लेकिन रहवासियों ने 24 मीटर तक चौड़ीकरण करना तकनीकी रूप से अनावश्यक बताते हुए इस पर आपत्ति लेते हुए कड़ा विरोध जताया है।

रहवासियों ने कहा कि मार्ग वर्तमान में लगभग 60 से 65 फीट चौड़ा है, जो 4-लेन सड़क के मानक के हिसाब से पर्याप्त है। नागरिकों का तर्क है कि 24 मीटर तक चौड़ीकरण करना तकनीकी रूप से अनावश्यक है। व्यापारियों ने चिंता जताई कि यह क्षेत्र पूर्णतः व्यावसायिक है और यदि चौड़ीकरण लागू हुआ, तो कई दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जमींदोज हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप करोड़ों की निजी संपत्ति का नुकसान और सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट आ सकता है। नागरिकों ने सड़क की सेंट्रल लाइन के निर्धारण पर भी सवाल उठाए हैं।

चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ठहाका महोत्सव का भव्य शुभारंभ

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ठहाका महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार शाम 7 बजे कालिदास अकादमी, उज्जैन में उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। लोकप्रिय कवि एवं अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन के संस्थापक एवं संयोजक डॉ. महेन्द्र यादव के नेतृत्व में विगत 26 वर्षों से ठहाका सम्मेलन का सफल आयोजन किया जा रहा है।

शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर शैलशानंद गिरी जी महाराज, अतिथियों के रूप में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय, योगेश शर्मा, मनीष शर्मा, महेश सीतलानी, दीपक बेलानी, कैलाश सोनी, जमना यादव एवं राजेन्द्र शाह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। 8 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले चार दिवसीय ठहाका महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन लोक, कला एवं साहित्य के विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजन के प्रथम दिन पोएट्री एवं कॉमेडी के ओपन माइक शो का आयोजन किया गया।

ठहाका महोत्सव का धमाकेदार आगाज़ ओपन माइक शो से हुआ। नए और उभरते कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस आयोजन को महोत्सव में शामिल किया गया। देशभर से आए 200 से अधिक प्रतियोगियों ने ऑडिशन दिया, जिनमें से 20 चयनित कलाकारों ने मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुतियाँ दीं।

ओपन माइक शो के सूत्रधार लोकप्रिय कवि राहुल शर्मा ने अपनी सशक्त वाणी, चुटीली शैली और वाकपटुता से पूरे सभागार को बांधे रखा और आयोजन में चार चांद लगा दिए।

उज्जैन समेत प्रदेश के 8 शहरों में वायु प्रदूषण बेकाबू, एनजीटी सख्त

प्रदूषण घटाने में नाकामी पर दिया नोटिस - 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। उज्जैन सहित प्रदेश के 8 शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के सरकारी प्रयासों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उज्जैन सहित प्रदेश के आठ शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। एनजीटी ने माना कि बीते पांच वर्षों में एयर क्वालिटी इंडेक्स घटने के बजाय और अधिक बढ़ा है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, सागर और सिंगरौली को वर्ष 2016 में नॉन-अटेनमेंट सिटी घोषित किया गया था, लेकिन अब तक वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी राज्यस्तरीय नीति लागू नहीं की गई। ट्रिब्यूनल ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली-एनसीआर जैसा प्लान नहीं, बढ़ता रहा प्रदूषण- एनजीटी ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मध्य प्रदेश में अब तक दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या एयर-शेड आधारित नीति लागू नहीं की गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि राजधानी भोपाल से लेकर उज्जैन तक प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। कई रातों में एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है।

पीएम-10 और पीएम-2.5 मानक से कई गुना ज्यादा- याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में पीएम-10 का पिछले पांच वर्षों का औसत 130 से 190 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जबकि इसका मानक स्तर 60 माइक्रोग्राम होना चाहिए। इसी तरह पीएम-2.5 का औसत 80 से 100 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया, जबकि इसकी सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला- मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदित्य दुबे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एयर-शेड एप्रोच अपनाने और क्षेत्रवार शॉर्ट, मीडियम व लॉन्ग टर्म उपाय लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में इन पर अमल नहीं किया गया।

सिंहस्थ में दो गुना से अधिक खपत होगी पानी की

शहर की वर्तमान व्यवस्था 151 से 400 एमएलडी तक जलशोधन क्षमता बढ़ाने का है टारगेट

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। उज्जैन की जलापूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में शहर में जल शोधन क्षमता 151 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) है, इसे बढ़ाकर 400 एमएलडी करने के लिए कई योजनाएं मंजूर हुई है। सिंहस्थ के दौरान करोड़ों लोग शहर आएंगे और इस दौरान जलापूर्ति के लिए वर्तमान से दो गुना से अधिक पानी की आवश्यकता होगी।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 6 लाख की आबादी वाला उज्जैन शहर गंभीर डेम के पानी पर आश्रित है। वर्तमान में उज्जैन की जल शोधन क्षमता 151 एमएलडी है। इसे बढ़ाकर 400 एमएलडी करने की कई योजनाएं मंजूर हुई है। अधिकारियों के मुताबिक यह विस्तार इसलिए जरूरी है क्योंकि शहर की वर्तमान आबादी करीब 6 लाख है, जबकि सिंहस्थ के दौरान लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान है। इतने बड़े जन दबाव को संभालने के लिए जल आपूर्ति ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

नए प्लांट व 17 टंकियां, बदली जाएंगी पुरानी लाइनें- योजना के तहत हरियाखेड़ी में 100 एमएलडी, अंबोदिया में 70 एमएलडी, गऊघाट में 30 एमएलडी सहित कुल चार बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही 17 नई उच्च स्तरीय जल टंकियों का निर्माण और करीब 500 किलोमीटर लंबी पुरानी मेन पाइपलाइन को बदलने की तैयारी है। गंभीर बांध और शिप्रा नदी पर नए इंटकवेल भी इस परियोजना का अहम हिस्सा हैं।

पुराने जल स्रोतों पर भी फोकस- जल संसाधन विभाग तथा पीएचई के अधिकारियों ने बताया कि योजना में जल स्रोतों को लेकर भी दीर्घकालिक रणनीति तय की गई है। वर्तमान में गंभीर, उंडासा और साहिबखेड़ी पर निर्भरता के साथ भविष्य में साहिबखेड़ी-सिलारखेड़ी जलाशय को जोड़े जाने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। अनेक परियोजनाओं पर काम भी शुरु हो गया है। इसके अलावा जरूरत पडने पर नर्मदा नदी से पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था भी योजना में शामिल है। इसके साथ ही नर्मदा-शिप्रा बहुउद्देशीय पाइपलाइन परियोजना से गंभीर की रॉ-वाटर लाइन जोडक़र गऊघाट तक पानी लाने की तैयारी भी की जा रही है।

बाइक सवार ने 14 साल के बालक को मारे चाकू

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। गुरुवार सुबह बाइक से आए युवक ने पैदल जा रहे नाबालिग को रोका और चाकू मार दिए। तीन चाकू लगने पर नाबालिग गंभीर घायल हो गया उसे लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जानसापुरा में रहने वाला उस्मान पिता मोहम्मद हुसैन 14 साल होटल पर काम करता है। सुबह वह पैदल घर से केडी गेट स्थित होटल जाने के लिए निकला था। रास्ते में बाइक सवार यासीन आया और उसने उस्मान को रोक लिया। यासीन ने गाली गलौज शुरू की और जेब से चाकू निकाल कर ताबड़तोड़ तीन वार कर दिए। उस्मान घायल हो गया और गिर पड़ा। लोगों ने उसे देखा और शोर मचाया तो चाकू मारने वाला भाग निकला। घायल उस्मान को चरक अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उपचार के लिए भर्ती किया है। बताया जा रहा है कि घायल और चाकू मारने वाले के बीच एक माह पहले विवाद हुआ था इसी के चलते उसे पर हमला हुआ है। जीवाजीगंज थाना पुलिस घायल के बयान दर्ज कर चाकू मारने वाले की तलाश कर रही है।

'अभ्युदय' में युवा प्रतिभा का उत्सवः संगीत, रंग और नृत्य से सजा पहला दिन

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव 'अभ्युदय' के पहले दिन सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य, चित्रकला और ज्ञान आधारित प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी रचनात्मक क्षमता और बौद्धिक कौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया। पूरे परिसर में कला, संस्कृति और युवा ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला।

कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज, कुलसचिव डॉ. अनिल शर्मा एवं विद्यार्थी कल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. एस.के. मिश्रा के मार्गदर्शन में उत्सव के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन आयोजित कार्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत की मधुर स्वर लहरियों से लेकर रंगों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा की अभिव्यक्ति तक, हर गतिविधि ने दर्शकों को आकर्षित किया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने यह स्पष्ट किया कि 'अभ्युदय' युवाओं के सर्वांगीण विकास और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने का प्रभावी मंच बन रहा है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद अभियांत्रिकी संस्थान में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव 'अभ्युदय' के प्रथम दिन एकल शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

उज्जैन में हुई आईसीएआई की करियर काउंसलर मीट

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की करियर काउंसलिंग कमेटी द्वारा करियर काउंसलर मीट का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी उज्जैन शाखा द्वारा की गई। उज्जैन शाखा के अध्यक्ष सीए आकृत जैन ने बताया कि करियर काउंसलिंग कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत में वाणिज्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, जिसमें विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य सभी संबंधित हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर आयोजित सेमिनार में करियर काउंसलिंग कमेटी के चेयरमैन सीए दुर्गेश काबरा (सीसीएम) एवं वाइस चेयरमैन सीए पंकज शाह (सीसीएम) विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ से पधारे सीए गौरव जगेटिया एवं सीए श्रेयस धारकर ने उपस्थित सभी करियर काउंसलरों का मार्गदर्शन किया तथा करियर काउंसलिंग के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

नापतौल विभाग ने बनाए 166 प्रकरण, 47 लाख से अधिक का राजस्व मिला

राजीनामा में ही वसूले साढ़े तीन लाख से अधिक

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नापतौल विभाग ने वजन में गड़बड़ी, बगैर सत्यापित कांटा बाट रखने सहित अन्य नियमों का पालन नहीं करने पर बीते 9 महीनों में कुल 166 प्रकरण बनाए हैं तथा संबंधित व्यापारियों से 47 लाख रुपए से अधिक का राजस्व वसूला हैं। इतना ही नहीं विभाग ने राजीनामा करने वाले व्यापारियों से साढ़े 3 लाख से अधिक की वसूली की है।

नापतौल विभाग के अधिकारी संजय पाटनकर ने बताया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच कुल 166 प्रकरण दर्ज किए हैं। इस अवधि में विभाग को लगभग 47 लाख 71 हजार 928 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ हैं, इसके साथ ही राजीनामा में 3 लाख 51 हजार 500 रुपये की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों का बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की टीम लगातार छापामार कार्रवाई करती रहती है। उपभोक्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उसे ठगने का प्रयास करें तो उसकी शिकायत करें। श्री पाटनकर ने बताया कि उपभोक्ता को अपने अधिकारियों का उपयोग करना चाहिए। सामान लेते वक्त पैकेट पर एमआरपी, पैकिंग दिनांक, कस्टमर केयर नंबर, घोषणा, कस्टमर केयर नंबर, प्रोडक्ट डिटेल आदि का उल्लेख होना चाहिए। इसी प्रकार खासकर मिठाई तौलते वक्त बॉक्स का वजन नहीं तौला जाना चाहिए। ऐसी बातों का ध्यान रखकर उपभोक्ता अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इसकी सूचना नापतौल विभाग को देना चाहिए।

शहर में पकड़े गए सबसे ज्यादा दुकानदार..- उल्लेखनीय है कि कम तौल या पदार्थ की पैकेट पर निर्धारित जानकारी नहीं लिखने पर नापतौल विभाग कार्रवाई करता है। ऐसे में 5 हजार से 25 हजार रुपए तक जुमनि का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल 2025 से अब तक कुल 166 अपराध प्रकरण दर्ज किए गये है। उज्जैन शहर में प्रमुख संस्थानों के जिसमें सब कुछ इंटरप्राइजेज, महामंगल किराना, राधारानी स्वीट्स, अंशु किन्तु नमकीन, वृंदावन रेस्टोरेंट, बांसुरीवाला नमकीन एंड स्वीट्स आदि दुकानों पर कार्रवाई की गई है।

श्री महाकाल की नगरी अवंतिका में विदेशी पक्षियों का डेरा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 के अंतर्गत उज्जैन के तालाबों में 67 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई। इस प्रकार श्री महाकाल की नगरी अवंतिका में विदेशी पक्षियों का डेरा हो गया है। जिला वनमण्डलाधिकारी श्री अनुराग तिवारी ने जानकारी दी कि यह उज्जैन के जैव विविधता के इतिहास का एक स्वर्णिम पल है। जानकारी अनुसार एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 के अंतर्गत उज्जैन के तालाबों में 3-4 जनवरी को उज्जैन जिले के विभिन्न तालाबों और जलाशयों में पक्षी सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे में कुल 67 पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गईं। यह सर्वे 17 बर्डवॉचर्स (पक्षी प्रेमियों) की टीम द्वारा किया गया, जिन्होंने अलग-अलग स्थानों पर उंडासा तालाब, सिलारखेड़ी तालाब,उज्जैन रोड क्षेत्र,गोगापुर क्षेत्र,पुरुषोत्तम सागर तालाब में गणना की गई। सर्वे के दौरान देखे गए प्रमुख पक्षियों में ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट, लेसर व्हिसलिंग डक, लिटिल स्विफ्ट, इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक, सारस क्रेन, पाइड बुशचैट, सिट्रीन वैगटेल, व्हाइट वेगटेल, लिटिल रिंग्ड प्लोवर, नॉर्दर्न शोवेलर, कॉमन सैंडपाइपर, वुड सैंडपाइपर, रूफस-टेल्ड लार्क, प्लेन प्रिनिया, यूरेशियन कूट, मोहन ग्रेन्स (मूरहेन) शामिल रहे।

पडोसी ने चुराये थे दवा कारोबारी के मकान से लाखों के आभूषण

पुलिस ने लिया हिरासत में आभूषण-नगदी बरामद करने का प्रयास

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। दवा कारोबारी के मकान में संदेहास्पद तरीके से हुई लाखों की चोरी के मामले में पड़ोसी आरोपी होना सामने आया है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जिससे पूछताछ कर चोरी किये आभूषण और नगदी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

नीलगंगा थाना क्षेत्र के ओम सांई अपार्टमेंट में रहने वाले मयूर पिता सुनील कुमार कृष्णानी दवा कारोबारी है। दवा बाजार में वह व्यवसाय करते है। 11 दिसंबर को उनकी पत्नी मायके रायपुर चली गई थी। इस दौरान मयूर कृष्णानी मकान का ताला लगाकर दवा बाजार चले जाते थे। 31 दिसंबर को पत्नी मायके से लौटी और रूपयों की आवश्कता होने पर चाबी मांगकर लॉकर खोला। उसमें रखे सोने-चांदी और डायमंड आभूषण लगभग लगभग 500 ग्राम, चांदी के सिक्के 500 ग्राम और 12 से 15 लाख केश गायब थे। बिना ताला टूटे हुए लाखों की चोरी से परिवार सकते में आ गया। उन्होने पहले घर में तलाश की लेकिन नहीं मिले। घर के सामने रहने वाले लविश टहलवानी के यहां लगे कैमरों के फुटेज देखने के लिये मांगे तो उसने रिकार्डिंग डिलीट होने की बात कहीं। उससे डीवीआर मांग गया और रिकार्डिंग रिकवर कराने की बात कहीं। वह आनाकानी करने लगा। जिसके चलते उस पर ही संदेह होने लगा। डीवीआर लेकर रिकार्डिंग कराने के लिये परिचित से संपर्क किया गया। इसी बीच लविश ने उक्त दुकानदार को कॉल कर जानकारी देने से मना कर दिया। इस बात का पता चलते ही मयूर को चोरी का पक्का संदेह पडोसी पर हो गया। मामले की शिकायत बुधवार को नीलगंगा थाने पहुंचकर की गई। पुलिस ने लविश को हिरासत में लिया तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार लाखों की चोरी का खुलासा होने पर आरोपित से पूछताछ कर माल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

चोरी के रूपयों से कर्ज चुकाया, खरीदा मोबाईल - बताया जा रहा है लविश का मयूरी के घर आना जाना था। उसे घर की जानकारी थी। उसने मकान की दो चाबी में से एक चाबी चोरी कर ली थी। 11 दिसंबर को मयूर की पत्नी के मायके जाते ही लविश ने चोरी की योजना बनाई। मसूरी भी सुबह से देर शाम तक दवा बाजार में प्रेम मेडिकल फार्मा पर रहते थे। इसी का फायदा उठाकर उसने चाबी से ताला खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

नगद राशि चोरी करने पर उसने अपना कर्ज उतारा, कुछ आभूषण बेच दिये और मोबाइल के साथ बाइक खरीद ली। पुलिस चोरी से खरीदे सभी सामान की बरामदगी का प्रयास कर रही है।